

विंध्य सत्ता

कड़ी मेहनत की आवाज़ होती है वह शब्दों की आवाज़ से ज्यादा जोरदार होती है।

वर्ष : 15 अंक: 147

रीवा, रविवार 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठ 12 मूल्य 4.00 रुपये

मध्यप्रदेश में निवेश आपको हर दृष्टि से लाभ देगा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मध्यप्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए लागू की गई नीतियों की दी जानकारी जीआईएस 2027 के लिये किया आमंत्रित

भोपाल, ब्यूरो।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश में निवेशकों से मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास की

प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर उन्हें हर स्थिति में लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को आंध्र प्रदेश में निवेशकों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेश के नए अवसरों और औद्योगिक साझेदारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी निवेशकों को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से वन-टू-वन



सहायक बन रही हैं। मध्यप्रदेश में धार जिले में पीएम मित्र पार्क और ग्वालियर में टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग इकाई में महत्वपूर्ण निवेश अब क्रियान्वयन की ओर है। हाल ही में जबलपुर-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर की

योजना तैयार की गई है। यह कॉरिडोर प्रदेश के बड़े व्यापक भू-भाग की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विजयवाड़ा में सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री विजय देवरकोंडा एवं अभिनेत्री श्रीमती रश्मिका मंदाना से भी भेंट हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में देश में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रदेश की फिल्म-फ्रेंडली नीतियां, फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने में सफल हुई हैं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को जीआईएस : 2027 का आमंत्रण देते हुए आयोजन की रूपरेखा की जानकारी दी जिसमें भोपाल में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक एकत्र होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी जिसमें 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए

संक्षिप्त समाचार

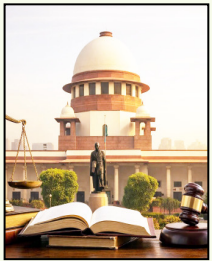
तमिलनाडु सीएम ने संगीतकार देवा को दी श्रद्धांजलि, फैस में शोक की लहर

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के



मुख्यमंत्री सी.जोसफ विजय ने शनिवार को दिग्गज संगीतकार और गायक देवा को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल का दौरा पड़ने के बाद चेन्नई के एक निजी अस्पताल में 76 वर्षीय देवा का निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने तुंगमबक्कम स्थित देवा के आवास का दौरा किया, जहां संगीतकार के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका यह दौरा फिल्म जगत और आम जनता के बीच शोक की लहर के बीच हुआ। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सिनेमा और संगीत में उनके योगदान को देखते हुए देवा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं के बारे में तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट बोला- बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका



नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना हर व्यक्ति, यहां तक कि बच्चों का भी मौलिक अधिकार है। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना बेतुका होगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और उनकी आजादी, दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा- इंटरनेट पर गलत कंटेंट होने के कारण बच्चों के लिए इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाना सही नहीं है। ऐसी रोक से बच्चे कम सुरक्षित वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। ऑनलाइन धमकी या शोषण का सामना करने वाले बच्चे शिकायत करने से भी डर सकते हैं। कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट (CSEAM) को पहचानने और हटाने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र को नेशनल डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसा कंटेंट हटाने के दो घंटे के भीतर पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को रिपोर्ट देनी होगी।

जंतर-मंतर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट की समिति ने प्रभावित लोगों से शिकायतें मांगीं

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (एचपीईसी) ने पहलुओं की जांच करने की जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर और अन्य शहरों में हुई हिंसा से जुड़ी घटनाओं से प्रभावित लोगों से शिकायतें और अभ्यावेदन आमंत्रित करने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार, प्रभावित लोगों और पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए पूर्व न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति ने एक पोर्टल शुरू किया है। प्रभावित लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें और संबंधित जानकारी समिति के सामने रख सकते हैं।

पांच सदस्यीय एचपीईसी को जुलाई में कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के जंतर-



जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अधिकारी ने बताया कि समिति 18 अगस्त और 10 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों में उल्लिखित मुद्दों की जांच करेगी। इसमें 18 अगस्त के आदेश

के पैरा 12 और 13 तथा 10 सितंबर के आदेश के पैरा 5(ड) में बताए गए विषय शामिल हैं।

समिति की प्राथमिकता में पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर हिंसा और उसीड़न किए जाने तथा दोनों पक्षों की ओर से अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामले शामिल होंगे।

गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, पोर्टल को इस तरह तैयार किया गया है कि संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रभावित व्यक्ति

चाहें तो अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध भी कर सकते हैं। प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायतें और अभ्यावेदन अपलोड करें।

केरल की अरुंधति ने सीएम योगी को लिखा भावुक पत्र, शादी में शामिल होकर आशीर्वाद देने का दिया न्योता

लखनऊ, एजेंसी। केरल की रहने वाली अरुंधति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो पन्नों का हस्तलिखित भावुक पत्र लिखकर अपनी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अरुंधति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल एक नेता नहीं, बल्कि बड़े भाई और प्रेरणास्रोत की तरह हैं। उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि बचपन में योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो से उन्हें जीवन की ऐसी सीख मिली, जिसने भावनाओं को देखने का उनका नजरिया बदल दिया।

अरुंधति का मानना था कि छोटी-

छोटी बातों पर भावुक होकर रोना कमजोरी की निशानी है। उनके कुछ दोस्त भी उन्हें समझाते थे कि मजबूत बनने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। धीरे-धीरे उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या आसानी से भावुक होने वाला व्यक्ति वास्तव में मजबूत हो सकता है और क्या अपनी भावनाएं व्यक्त करने में शर्म महसूस करनी चाहिए। इसी दौरान उनके एक



चचेरे भाई ने उन्हें योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो दिखाया। वीडियो में योगी आदित्यनाथ भावुक नजर आ रहे थे।

उनके भाई ने अरुंधति को समझाया कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो भावुक होने के बावजूद बेहद मजबूत हैं।

इस वीडियो ने अरुंधति की सोच बदल दी। उन्हें समझ आया कि आंसू किसी व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण नहीं हैं। भावनात्मक संवेदनशीलता मानवीय करुणा और संवेदना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इस सीख ने उन्हें अपने भीतर चल रहे द्रढ़ से बाहर निकलने में मदद की।

राहुल गांधी के खिलाफ महिला पत्रकार ने दर्ज कराई शिकायत, तुरंत FIR की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी।

राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ महिला पत्रकार ऋचा पराशर ने शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत नई दिल्ली के डीसीपी के पास की गई है। शिकायत में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष समेत सभी पर तुरंत एफआईआर की मांग की है।राहुल गांधी के खिलाफ महिला पत्रकार ऋचा पराशर ने



नई दिल्ली के डीसीपी के पास एक शिकायत दर्ज की है। इसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य के खिलाफ तुरंत खट्टकरी

तर्फ से की गई शिकायत में BNSS 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

भारत की आर्थिक वृद्धि

भारत का लगातार 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज करना मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का संकेत : शीर्ष अर्थशास्त्री

नई दिल्ली, एजेंसी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक समेत लगभग सभी प्रमुख संस्थानों ने हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को बढ़ाकर इस साल और अगले साल के लिए 7 प्रतिशत से अधिक कर दिया है। यह बयान प्रमुख अर्थशास्त्री क्युतून किम ने दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में किम ने कहा कि वृद्धि के अनुमानों में यह बढ़ोतरी अपने आप में महत्वपूर्ण है और भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दिखाता है।

भारत की आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में 5.8 प्रतिशत की गिरावट आने के बाद 2021 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके

बाद अगले लगातार चार वर्षों में अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ी।

उन्होंने कहा कि उनके समेत कई अर्थशास्त्रियों ने तिमाही जीडीपी के आंकड़े सामने आने के साथ बार-बार आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को बढ़ाया।

किम ने कहा, 'इस तरह भारत ने लगातार पांच वर्षों तक 7 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। यह 2003-2007 के दौर के बराबर है, जब भारत ने ब्रिक (बीआरआईसी) अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। यदि मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं, तो भारत इस रिकॉर्ड को भी पीछे



छोड़ देगा। '

उन्होंने बताया कि 2021 से 2025 के दौरान भारत की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7.83 प्रतिशत रही। 1960 से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह किसी भी पांच साल की अवधि की दूसरी सबसे ऊंची औसत वृद्धि दर है। इससे पहले 2003-2007 के दौरान 7.89 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई थी। अर्थशास्त्री के अनुसार,

कई वर्षों तक इस तरह की आर्थिक वृद्धि की गति बनाए रखना विशेष ध्यान देने योग्य है। किम ने कहा, 'आज भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। 2007 में भारत की जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर से थोड़ी अधिक थी, जबकि अब यह लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर के करीब है। इस कारण 7 प्रतिशत की समान वृद्धि दर का मतलब आज अर्थव्यवस्था का कहीं अधिक बड़ा विस्तार है। '

उन्होंने आगे कहा, 'कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन 1.4 अरब लोगों वाले देश का यह आर्थिक प्रदर्शन जश्न मनाने योग्य है। मुझे उम्मीद है कि अगली तिमाही के जीडीपी आंकड़े आने पर प्रमुख संस्थानों के अर्थशास्त्री और मैं एक बार फिर अपने आर्थिक वृद्धि अनुमानों में कुछ दशमलव अंकों की बढ़ोतरी करेंगे। '

चचाई। 600 मेगावाट प्लांट में मजदूर को लगा करंट, चेहरा झुलसा

गंभीर हालत में जबलपुर रेफर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

विंध्य सत्ता,चचाई। चचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन 600 मेगावाट के प्लांट में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्लांट में महारेला कंपनी और बीबीजी कंपनी के कार्य से जुड़े मजदूर धनंजय यादव, निवासी कानपुर, उत्तर प्रदेश, के साथ 16 अक्टूबर को करंट लगने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि करंट की चपेट में आने से मजदूर का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद आनन-फानन में घायल मजदूर को शहडोल स्थित श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद निर्माणाधीन प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कार्यस्थल पर ऐसा क्या हुआ कि एक मजदूर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया? क्या प्लांट में बिजली से संबंधित कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे? इन सवालों के जवाब संबंधित कंपनी प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों को देने चाहिए।

सुरक्षा इंतजामों में चूक या निगरानी की कमी मजदूर की गंभीर हालत ने खड़े किए सवाल

निर्माणाधीन औद्योगिक परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बिजली से जुड़े कार्यों के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती, आवश्यक सुरक्षा उपकरण, विद्युत आपूर्ति को सुरक्षित तरीके से बंद करने की प्रक्रिया और कार्यस्थल पर सतत निगरानी बेहद जरूरी होती है। ऐसे में यदि किसी



मजदूर के करंट की चपेट में आने की घटना सामने आती है, तो यह पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक, धनंजय यादव के साथ हुई घटना में उसका चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उसे तत्काल शहडोल के श्रीराम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां हालत गंभीर होने के कारण उसे जबलपुर रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह मामला केवल एक दुर्घटना तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के इंतजामों और आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता भी सामने लाता है।

थाने में सूचना दी गई या नहीं? घटना की जानकारी को लेकर भी उठे सवाल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के संबंध में चचाई थाने में सूचना दिए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित पुलिस थाने और अन्य जिम्मेदार विभागों को घटना की जानकारी दी गई थी या नहीं। यदि सूचना नहीं दी गई, तो इसके कारणों की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी

पता लगाया जाना चाहिए कि दुर्घटना के बाद कंपनी प्रबंधन ने क्या कदम उठाए, घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाने में कितनी तत्परता दिखाई गई और क्या कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार तथा आपातकालीन चिकित्सा सहायता की समुचित व्यवस्था मौजूद थी। इन बिंदुओं की जांच से ही वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकेंगी।

मजदूरों की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित तो नहीं

बड़े औद्योगिक प्लांटों में निर्माण कार्य के दौरान अनेक मजदूर अपनी मेहनत से परियोजनाओं को आकार देते हैं। लेकिन यदि कार्यस्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होंगे, तो छेटी-सी चूक भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले मजदूर भी अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए जोखिम भरे कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित कंपनी, ठेकेदार और कार्यस्थल पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मजदूरों को काम शुरू करने से पहले सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या उन्हें कार्य के अनुरूप आवश्यक दस्ताने, सुरक्षा जूते, हेलमेट और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं? क्या विद्युत कार्यों की नियमित जांच होती है? क्या प्लांट में सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं और क्या वे निर्धारित नियमों के अनुसार निरीक्षण करते हैं? यदि इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो उसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुधार किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य मजदूर की जान जोखिम में न पड़े।

आखिर जवाबदेही किसकी—कंपनी प्रबंधन,

ठेकेदार या सुरक्षा अधिकारियों की

धनंजय यादव के साथ हुई बताई जा रही घटना ने कंपनी प्रबंधन और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों और संभावित लापरवाही की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि संबंधित विभाग घटनास्थल की परिस्थितियों की जांच करें और यह पता लगाएं कि दुर्घटना के समय किस प्रकार का कार्य कराया जा रहा था, सुरक्षा के कौन-कौन से इंतजाम मौजूद थे और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी किसके पास थी। यदि जांच में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन या लापरवाही की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही घायल मजदूर को उपचार और नियमानुसार मिलने वाली सहायता के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग, प्लांट प्रबंधन से मांगा जाए जवाब

चचाई थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन 600 मेगावाट के प्लांट से जुड़ी इस घटना को देखते हुए संबंधित श्रम विभाग, विद्युत सुरक्षा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को मामले की जांच करनी चाहिए। मजदूरों की सुरक्षा के लिए लागू नियमों के पालन की समीक्षा होनी चाहिए और यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि घटना के बाद संबंधित विभागों को सूचना दी गई थी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निर्माणाधीन प्लांट में मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे, तो धनंजय यादव किन परिस्थितियों में करंट की चपेट में आया? और यदि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी, तो उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी।

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में बुद्धार पुलिस की कार्रवाई



मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार

विंध्य सत्ता,शहडोल। जिले में नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुद्धार थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सहित तीन अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी कोदूलाल भरिया, निवासी ग्राम हरी चौकी, केशवाही के विरुद्ध बुद्धार थाने में भारतीय न्याय संहिता (बोएनएस) एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

निर्देशों के पालन में बुद्धार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य आरोपी कोदूलाल भरिया (33), कुनालाल भरिया (55), विपिन भरिया उर्फ कब्बू (19) और राजकुमार भरिया (20) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम हरी चौकी, केशवाही क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।

पुलिस की कार्रवाई, विवेचना जारी

पुलिस के अनुसार, मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्रकरण की विवेचना जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जंगल में पेड़ से गिरने पर युवक की मौत

पत्नी की आंखों के सामने थमीं सांसें, लकड़ी बीनने गए थे दंपती

विंध्य सत्ता,शहडोल। जंगल में लकड़ियां बटोर रही पत्नी की नजरें बार-बार पेड़ पर चढ़े पति की ओर जा रही थीं। जब लकड़ियां पर्याप्त हो गईं तो उसने आवाज लगाई- बस करो, अब नीचे उतर आओ, घर चलते हैं। पत्नी को क्या पता था कि कुछ ही पल बाद उसकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा छा जाएगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। पति पेड़ से नीचे उतर ही रहा था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। पत्नी दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन पति गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वह मदद के लिए चीखती रही, मगर घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही देर में पति की सांसें थम गईं। यह दर्दनाक घटना शहडोल जिले के गोहापारु थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, रतहर निवासी 32 वर्षीय सुखीलाल कोल अपनी पत्नी के साथ गांव के पास स्थित बहेहा जंगल में लकड़ी

काटने गया था। पति पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था, जबकि पत्नी नीचे खड़ी होकर गिराई गई लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी।

पत्नी की आंखों के सामने जिंदगी की जंग हर गया पति

पत्नी के मुताबिक, जब काफी लकड़ियां इकट्ठा हो गईं तो उसने पति से कहा कि अब बस करो और नीचे उतर आओ। घर लौटने की तैयारी के बीच सुखीलाल पेड़ से उतर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। पति को जमीन पर घायल पड़ा देख पत्नी चकरा गई। वह तत्काल उसके पास पहुंची और मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह बार-

बार पति के पास जाती और किसी के आ जाने की उम्मीद में जंगल की ओर देखती रही। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मदद मिले और पति को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन उस वक्त जंगल में दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। पत्नी की आंखों के सामने ही सुखीलाल ने दम तोड़ दिया।

राहगीरों के पहुंचने तक हो चुकी थी देर

कुछ समय बाद जंगल के रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पत्नी की चीख-पुकार सुनी और मौके पर पहुंचे। हालांकि, तब तक सुखीलाल की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर गोहापारु पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरहा की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

जन आरोग्य समिति की बैठक में शिकायत दर्ज,कार्रवाई का इंतजार

विंध्य सत्ता,खैरहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरहा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच अब साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 5 अगस्त 2026 को आयोजित जन आरोग्य समिति की बैठक की हस्तलिखित कार्यवाही में नियमित साफ-सफाई नहीं होने और आउटसोर्स कर्मचारी की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतों रहने का आरोप लगाया गया है। व्यवस्था में सुधार के लिए वैकल्पिक सफाई कर्मचारी रखने का प्रस्ताव भी दर्ज किया गया। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका चर्चा में है।

नियमित सफाई नहीं होने की शिकायत, कर्मचारी की कार्यप्रणाली पर सवाल

बैठक की कार्यवाही के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी राज नापित की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष



जाता गया है। शिकायत में नियमित साफ-सफाई नहीं होने और कर्मचारी के अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों के अनुसार, कर्मचारी की इड्यूटी और रात में अस्पताल में रुकने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है और संबंधित कर्मचारी का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है।

बीएमओ सिंहपुर को आवेदन, कार्रवाई का इंतजार

अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में बीएमओ सिंहपुर डॉ. पुष्येंद्र सिंह को आवेदन देकर संबंधित कर्मचारी के

विरुद्ध कार्रवाई करने तथा सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। इसके बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिकायत पर जांच की स्थिति क्या है और मरीजों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।

वैकल्पिक कर्मचारी रखने का प्रस्ताव, अब अमल की बारी

जन आरोग्य समिति की बैठक में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से राकेश कुमार हरिजन को सफाई कर्मचारी के रूप में रखने का प्रस्ताव दर्ज किया गया। बैठक में अस्पताल की बिजली व्यवस्था एवं जनरेटर की मरम्मत और मरीजों के बैठने के लिए दो रिक्लाईनिंग कुर्सियां तथा एक ग्री-सीटर कुर्सी खरीदने पर भी चर्चा की गई। हालांकि, प्रस्ताव दर्ज होना और उस पर अमल होना अलग-अलग विषय हैं। अब देखना होगा कि संबंधित

प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग कब निर्णय लेता है और सफाई व्यवस्था को नियमित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

स्वास्थ्य विभाग से उठ रहे पांच अहम सवाल

* प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित सफाई की निगरानी कौन कर रहा है * आउटसोर्स कर्मचारी की कार्यप्रणाली को लेकर की गई शिकायत की जांच कब होगी * बीएमओ सिंहपुर को दिए गए आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई वैकल्पिक सफाई कर्मचारी रखने के प्रस्ताव पर कब तक अमल होगा * मरीजों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तय कर नियमित निगरानी कब शुरू होगी अब कार्रवाई से तय होगी व्यवस्था की हकीकत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरहा में सफाई व्यवस्था को लेकर उठी शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीरता से जांच करने का विषय हैं। अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखना मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे में केवल बैठक में प्रस्ताव दर्ज करना पर्याप्त नहीं, बल्कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच, संबंधित कर्मचारी का पक्ष सुनना और जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

खास खबर

एसईसीएल सोहागापुर क्षेत्र की बैठकों में करेंगे प्रतिनिधित्व

विंध्य सत्ता,धनपुरी। शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने एसईसीएल सोहागापुर क्षेत्र से संबंधित बैठकों के लिए धनपुरी निवासी विनय सिन्हा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस संबंध में सांसद ने एसईसीएल सोहागापुर क्षेत्र के महाप्रबंधक को आधिकारिक पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। सांसद के इस निर्णय को क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने और बैठकों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। सांसद हिमाद्री सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जिन बैठकों में वह स्वयं उपस्थित नहीं रह पाएंगी, उन्में विनय सिन्हा उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर निर्धारित दायित्वों का निर्वहन

करेंगे। यह जिम्मेदारी विनय सिन्हा को क्षेत्र से जुड़े विषयों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी।

सांसद हिमाद्री सिंह की पहल, प्रतिनिधित्व को लेकर स्पष्ट संदेश

सांसद हिमाद्री सिंह द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि उनकी अनुपस्थिति में भी एसईसीएल सोहागापुर क्षेत्र की बैठकों में उनका प्रतिनिधित्व बना रहे। स्थानीय स्तर पर इस पहल के माध्यम से क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर संवाद और समन्वय को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। सांसद की ओर से जारी

आधिकारिक पत्र उनकी इस व्यवस्था की पुष्टि करता है। क्षेत्रीय विषयों को बैठकों में स्थान दिलाने के लिए प्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ताकि संबंधित मामलों पर चर्चा और आवश्यक जानकारी का आदान-प्रदान हो सके।

विनय सिन्हा को मिली जिम्मेदारी, भरोसे पर खरा उतरने की अपेक्षा

धनपुरी के वार्ड क्रमांक-21, बाजार रंगमंच निवासी विनय सिन्हा को मिली यह जिम्मेदारी उनके लिए



महत्वपूर्ण अवसर है। सांसद की ओर से प्रतिनिधित्व सौंपे जाने के बाद उनसे अपेक्षा रहेगी कि वह बैठकों में क्षेत्र से जुड़े विषयों को गंभीरता से

रखें और सौंपे गए दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। विनय सिन्हा के लिए यह अवसर केवल प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने तक सीमित नहीं, बल्कि संबंधित बैठकों में विषयों को समझने, अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को उचित मंच तक पहुंचाने का माध्यम भी बन सकता है।

सांसद और विनय सिन्हा की भूमिका पर टिकी क्षेत्रवासियों की उम्मीदें

सांसद हिमाद्री सिंह की ओर से जिम्मेदारी सौंपे जाने और विनय सिन्हा को प्रतिनिधित्व मिलने के बाद क्षेत्रवासियों की उम्मीद है कि एसईसीएल सोहागापुर क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद को मजबूती मिलेगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैठकों में क्षेत्रीय मुद्दों को किस प्रकार उठाया जाता है और संबंधित विषयों पर आगे क्या पहल होती है। सांसद हिमाद्री सिंह की इस पहल और विनय सिन्हा को सौंपी गई जिम्मेदारी से क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय की एक व्यवस्था बनी है। दोनों की भूमिका के माध्यम से जनहित से जुड़े विषयों को उचित मंच तक पहुंचाने की दिशा में सकारात्मक प्रयासों की अपेक्षा की जा रही है।

डिटी कमिश्नर ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण।



विंध्य सत्ता,शहडोल। शहडोल संभाग में चलाए जा रहे स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान के अंतर्गत शहडोल संभाग में भी लगभग 9890 हितग्राहियों को इस अभियान अंतर्गत रजिस्ट्र किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शहडोल संभाग की कमिश्नर श्रीमती सुरेश गुप्ता के द्वारा लगातार स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान के

अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा रही है। कमिश्नर ने डिटी कमिश्नर श्री हनुंद्र चोरमारे तथा शहडोल संभाग के संभागीय सलाहकार आर सी एम एस श्री उषेंद्र त्रिपाठी को निरीक्षण कर प्रगति लाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसी अनुक्रम में डिटी कमिश्नर राजस्व ,संभागीय सलाहकार आर सी एम एस ने सोहागापुर तहसील के बोदरी ग्राम तथा बुद्धार के खमरोध तथा बाटूरा ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शहडोल संभाग की कमिश्नर श्रीमती सुरेश गुप्ता के द्वारा लगातार स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान के

बनाया गया है। दुर्घटना के बाद जैसे ही पुलिस में अज्ञात वाहन के खिलाफ प्रारंभिकी दर्ज होती है, पॉइंट के निकटमा वारिस संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या दवावा जांच अधिकाारी के पास आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दवावाकर्ता के बैंक खाता की छायाप्राप्ति, अस्पताल में उपचार कराने के बिल, दवावा तथा मृतक की पहचान तथा पावा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिथिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ पुलिस में दर्ज एकआईआर की प्राप्ति, दवावा करने वाले की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र, मौत की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं गंभीर चोट होने पर एमएलसी रिपोर्ट देना आवश्यक होता है।

ब्रीफ न्यूज़

दशहरे के पहले सरकार लेगी 4500 करोड़ का कर्ज

भोपाल। लाइली बहना योजना में दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू करने के दावे-प्रतिदावे के बीच मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए सरकार ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनमें 1000 करोड़, 2000 करोड़ और 1500 करोड़ रुपए के ऋा शामिल हैं। तीनों ऋणों की नीलामी 19 अक्टूबर 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय में ई-कुबरे के माध्यम से होगी। सरकार चार साल, 12 साल और 22 साल की अवधि के लिए अलग-अलग ऋण लेगी। इनमें एक नया चार वर्षीय ऋण, 12 साल की अवधि वाली पहले जारी सरकारी प्रतिभूतियों का पुनः निर्गम और 22 साल की अवधि का ऋा शामिल है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत सरकार की वार्षिक उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपए बताई गई है। पहले नौ महीने के लिए 58 हजार 274 करोड़ रुपए की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत हुई है। सरकार चार साल की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी।

जीएंडी के अस्पष्ट आदेश से फीस निर्धारण समिति टप

भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएंडी) द्वारा जारी एक अस्पष्ट आदेश ने प्रदेश में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के फीस निर्धारण की पूरी व्यवस्था को टप कर दिया है। 16 सितंबर को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) के पुनर्गठन का आदेश जारी हुए पूरा एक महीना बीत चुका है, लेकिन समिति की अब तक पहली औपचारिक बैठक तक नहीं हो सकी है। इसका कारण सामने आया कि जीएंडी ने कमेटी में बिना एक्ट के सदस्यङ्कसचिव का पदनाम जोड़ दिया। यह पदनाम तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक या अतिरिक्त संचालक के लिए जोड़ा गया। जबकि पहले केवल सदस्य हुआ करता था। यह गलती पकड़ में आते ही पहले कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन और फिर चेयरमैन के ओएसडी की तरफ से जीएंडी को पत्र भी भेजे गए, लेकिन अब तक इस पर सुधार नहीं हुआ।

राम मंदिर ट्रस्ट और वोट चोरी पर दिग्विजय के आरोप

इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े होने और अब वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2 करोड़ रुपए की जमीन अगले ही दिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेची गई। शनिवार को इन्हें प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान सिंह ने ट्रस्ट के जमीन सौदों, चंदे और निर्माण कार्यों की जांच की मांग की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (रखुऊ) पर भी सवाल उठाए और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण और जमीन की खरीद में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।सिंह ने ट्रस्ट की भूमिका और कामकाज की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर प्रबंधन में धार्मिक परंपराओं से जुड़े प्रतिनिधियों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

ओबीसी आरक्षण पर आमने-सामने कांग्रेस-भाजपा

जबलपुर। एमपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में आरक्षण के पक्ष में मजबूती से दलीलें नहीं रखीं और न ही जरूरी आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण के मामले में धोखा देने का आरोप लगाया है। शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे विवेक तन्खा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण 14ब से बढ़ाकर 27ब किया था। हालांकि, इसे अदालत में डिफेंड करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की थी, क्योंकि बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा सत्ता में आ गई। तन्खा ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने स्पष्ट किया था कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50ब होती है। इससे अधिक आरक्षण देने के लिए सरकार को साधारण परिस्थितियों के समर्थन में मात्रात्मक आंकड़े (क्रॉटिफायबल डेटा) प्रस्तुत करने होते हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से लगता है कि सरकार पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर पाई। यदि जरूरी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते, तो संभव है कि फैसला अलग होता।

ग्वालियर-ऊज्जैन समेत 21 जिलों में आज बारिश, एमपी में दो चक्रवात का असर

अगले 4 दिन सागर, जबलपुर संभाग भी भीगेंगे

नगर संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बारिश का दौर अब भी जारी है। पिछले दो दिनों से ग्वालियर, चंबल और ऊज्जैन संभाग में बारिश हो रही है। मौसम केंद्र भोपाल ने शनिवार को प्रदेश के 21 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में ग्वालियर, ऊज्जैन, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, रतलाम, झाबुआ, धार, आलीराजपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्यापुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं। इसके चलते अगले 4 दिनों तक ग्वालियर, चंबल, ऊज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, रीवा और जबलपुर संभाग के जिलों में मौसम बदला रहेगा। 18 और 19 अक्टूबर को नीमच, मंदसौर, श्यापुर,



शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सीधी, मऊगंज, सिंगरीली, सिवनी और बालाघाट में बारिश होने का अनुमान है। 20 अक्टूबर से मौसम प्रणाली कमजोर पड़ने लगेगी। इसके बाद तेज बारिश की संभावना नहीं है।

इससे पहले गुरुवार को चंबल और ऊज्जैन संभाग के उत्तरी 5 जिले- श्यापुर, भिंड, मुरैना, नीमच और मंदसौर में

बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, शुक्रवार को भी मौसम बदला रहा। दूसरी ओर, कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। अनुपपुर के अमरकंटक में 16.6 डिग्री, छिंदवाड़ा में 17.4 डिग्री, इंदौर में 17.6 डिग्री, कटनी के करौंदी में 18 डिग्री और बैतूल में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रदेश से 3 अक्टूबर को ही मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम

प्रणाली सक्रिय होने के कारण बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। पिछले एक सप्ताह से पूर्वी हिस्से के जिलों में आंधी-बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर में बारिश, गर्मी और ठंड तीनों का असर देखने को मिलता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम साफ हो गया था और धूप खिलने लगी थी। वहीं, रात में ठंडक महसूस हो रही है और कई जिलों में बारिश भी हो रही है। इस बार प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून करीब 100 दिन तक सक्रिय रहा है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान प्रदेश में कुल 908.4 मिमी यानी, 35.8 इंच (95.9 प्रतिशत) बारिश हुई। यह सामान्य बारिश 37.3 इंच (949.5 मिमी) की तुलना में 1.5 इंच कम है। वहीं, ओवरऑल 4 प्रतिशत कम पानी गिरा। पूर्वी हिस्से में 4ब ज्यादा और पश्चिमी हिस्से में औसत से 12ब बारिश कम हुई है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से- जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में आंकड़ा चार

इन 25 जिलों में बारिश का कोटा फुल

भोपाल, राजगढ़, बुरहानपुर, खरगोन, कटनी, मंडला, डिंडोरी, ग्वालियर, गुना, दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर, आगर-मालवा, भिंड, श्यापुर, सिंगरीली, सीधी, सतना, मऊगंज, शहडोल, उमरिया और अनुपपुर में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। वहीं 30 जिलों में कम बारिश हुई। इनमें नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट, अशोकनगर, मुरैना, मंदसौर, खंडवा, बड़वानी, नीमच, जबलपुर, रीवा, सागर, सिवनी, सीहोर, शिवपुरी, रायसेन, छिंदवाड़ा, विदिशा, शाजापुर, पांडुवा, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार और आलीराजपुर शामिल हैं।

प्रतिशत ज्यादा है। अधिकांश जिलों में कोटे से ज्यादा पानी गिर चुका है, लेकिन बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, पांडुवा, रीवा, सागर, सिवनी में 5ब से 21ब तक कम बारिश हुई है।

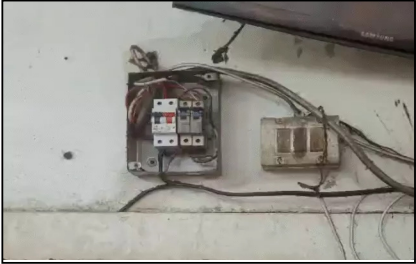
900 दुकानों के बीच सुलग रही भट्टियां, एनओसी नहीं

भोपाल के न्यू मार्केट में खतरे के बीच छोले-भटूरे खा रहे लोग 50 फीट में 3 दुकानें

नगर संवाददाता

भोपाल। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में कपड़ा, ज्वैलर्स समेत करीब 900 दुकानों के बीच भट्टियां भी सुलग रही हैं। जिस छोले-भटूरे की दुकान में 8 अक्टूबर को भीषण आग लगी, वहां से सिर्फ 50 फीट दूर ही 3 दुकानें और हैं। यहां खतरे के बीच ही भटूरे तले जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि इन दुकानों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। दुकान की न तो फायर और न ही इलेक्ट्रिक एनओसी है। फायर एक्सटिंग्विशर जरूर हैं, लेकिन कोने में रखे हैं। यदि आग लग जाए तो इन्हें चलाने के लिए कर्मचारी भी प्रशिक्षित नहीं हैं। जिस जगह पर छोले तले जा रहे, उसके ऊपर ही धूप से बचने के लिए ट्रिक्टेबल अर्वानिंग लगी है। जरूरत के हिसाब से इसे खोल और बंद कर सकते हैं। यहां आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर तो है, लेकिन इन्हें चलाना नहीं आता। यहां किचन इतना छोटा है कि 2 कर्मचारी मुश्किल से बैठकर भटूरे तलते हैं। ऐसे में आग लग जाए तो कर्मचारी निकल ही नहीं सकते। बिजली के तार भी खुले हुए हैं।

फायर और इलेक्ट्रिक एनओसी नहीं मिली। कई जगहों से बिजली के तार खुले मिले। फायर एक्सटिंग्विशर तो है, लेकिन कोने में रखे हैं। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि दुकान में अग्निशामक यंत्र होने



चाहिए। कर्मशियल सिलेंडर ही होना चाहिए। भट्टियां नहीं होना चाहिए। जांच में सामने आया कि भट्टियां पाई गईं। देहली के छोले-भटूरे में ऊंचाई पर बैठकर कर्मचारी भटूरे तलते हुए मिला। इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। बिजली के तार भी खुले ही पड़े हैं। इन सभी खामियों के चलते दुकानों को शिफ्ट करने का प्लान है। बालाजी छोटे

भटूरे दुकान में 8 अक्टूबर को भीषण आग लगी थी। आग ने पास की 5 बड़ी दुकानों और 12 से ज्यादा रेहडिग्रियों को चपेट में ले लिया था। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। जिस जगह आगजनी हुई थी, उससे

100 फीट की दूरी पर ही दो और छोले भटूरे की दुकानें खुली हुई हैं। इसके पास में दो से तीन नमकीन दुकानें भी हैं। जहां पर सुबह से रात तक भट्टी जलती है। ऐसे में फिर से हादसा होने की संभावना है। 8 अक्टूबर को बालाजी छोला भटूरे दुकान में आग लगी थी और इसके बाद पास की अन्य दुकानें भी चपेट में आ गई थीं। इस मामले में टीटी नगर पुलिस ने आम्नपाली रेस्टोरेंट के संचालक पवन अग्रवाल की

शिकायत पर छोला भटूरे की दुकान के संचालक दीप उर्फ दीपू अग्रवाल के विरुद्ध केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि बालाजी छोला-भटूरा दुकान में भट्टी जल रही थी। इसके पास रखे कपड़े में आग लगने के बाद लपटें फैल गईं और देखते ही देखते आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं।

भोपाल में यौन हिंसा के बाद बच्ची का गला घोंटा, सीसीटीवी में मासूम संग दिखा आरोपी

नगर संवाददाता

भोपाल। भोपाल में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के बाद शनिवार को 3 घंटे विरोध प्रदर्शन हुआ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उनका कहना था कि पुलिस आरोपी मोबिन को फांसी दे या हमें सौंपे। हम उसे सजा देंगे। भीड़ ने थाने में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने थाने के गेट पर धक्का-मुक्की भी की। हालांकि, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं

वारदात वाली रात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बच्ची को ले जाते हुए और कुछ देर बाद अकेले निकलते हुए दिख रहा है। बात दें बैरागढ़ में 15 अक्टूबर यानी गुरुवार रात से लापता बच्ची का

शव 16 अक्टूबर को कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे खंडहर में मिला था। उसके सामने के दो दांत टूटे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा,



गला घोंटने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा है कि उसने भी जुर्म कबूल कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने भोपाल-सीहोर रोड पर जाग लगा दिया था। प्रदर्शनकारी हटने को

तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि आरोपी को बीच सड़क पर फांसी दी जाए। उसके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। जांच के कारण करीब 2 किलोमीटर तक वार्डनों की कतार लगी रही।

मामले में एसीपी रबेश तोमर का कहना था कि पुलिस ने हत्या और बहला-फुसलाकर ले जाने सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। विस्तृत

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर अतिरिक्त कानूनी धाराएं जोड़ी जाएंगी। परिजन अंतिम संस्कार के लिए बच्ची के शव को घर गए। फिलहाल, प्रदर्शन शांत है। एहि्तयात के तौर पर पुलिस बल तैनात है। एसीपी रबेश तोमर ने कहा- एक खाली इमारत से बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या और बहला-फुसलाकर ले जाने सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

भोपाल में जुटेंगे 1000 क्रिएटर्स, अवॉर्ड शो होगा

नगर संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश के बड़े क्रिएटर सम्मेलनों में शामिल भोपाल क्रिएटर्स समिट 2026 का चौथा संस्करण 24 अक्टूबर को होटल ताज में होगा। इसमें देशभर से 1000 से अधिक क्रिएटर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स, संगीतकारों, डांसर्स, गेमर्स, कलाकारों और मनोरंजन जगत से जुड़े प्रतिभाशाली लोग एक मंच पर जुटेंगे। समिट का उद्देश्य देश के क्रिएटर इकोसिस्टम को मजबूत करना, उभरती प्रतिभाओं को पहचान दिलाना और मध्य प्रदेश को कला, संस्कृति एवं डिजिटल क्रिएटिविटी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस वर्ष के समिट का प्रमुख आकर्षण क्रिएटर्स अवॉर्ड शो होगा। जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री क्रिएटर्स को सम्मानित करने के साथ उनसे संवाद भी करेंगे। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल क्रिएटर्स और सरकार के बीच संवाद को बढ़ावा देना तथा क्रिएटर समुदाय के योगदान को प्रोत्साहित करना है। पैनल चर्चाओं के माध्यम से कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मीडिया, ब्रांड कॉलेबोरेशन, मार्केटिंग, मनोरंजन उद्योग और क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध नए अवसरों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।



मोतीलाल ओसवाल के नाम पर GNS फाइनेंशियल सर्विसेज बुद्धार पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप..?

मोतीलाल ओसवाल के नाम पर निवेश का प्रलोभन देने की शिकायत, पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग; कोतमा से भालूमाड़ा तक निवेशकों की शिकायतों से उठे सवाल..!

इंट्रो

शहडोल,, बुद्धार,,धनपुरी,, नरोजाबाद पाली,कोतमा,, भालूमाड़ा,,जमुना,,पसान,, बिजुरी,, रामनगर,, मनेंद्रगढ़,, छत्तीसगढ़ तक फैला मोतीलाल ओसवाल के नाम पर GNS financial services में राशि परिवर्तन कर निवेशकों के साथ पैसे की धोखाधड़ी कर, फैलाया एमपी सीजी में ठगी का मकड़जाल। चिटफंड कंपनी ने लगभग 800 सी करोड़ रुपए की हेराफेरी कर हजारों निवेशकों का पैसा धोखाधड़ी कर हड़पने के बाद अपनी लूट की दुनाक बुद्धार,,कोतमा,, मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में खुले आफिसों में ताला जड़ कर कम्पनी के संचालक ,,ब्रांच मैनेजर सहित सैंकड़ों स्थानीय एजेंट कब निवेशकों के साथ लुका छिपी का खेल रच रहे हैं,,इन ठगबाजों को पकड़ कर कार्रवाई करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज, कारण इनकी पहुंच पकड़ बड़े-बड़े लोगों से होना बताया जा रहा है।

सिक्की मिश्रा जिला ब्यूरो

कर एफआईआर दर्ज करने और न्याय दिलाने की मांग की है। अधिक मुनाफे का लालच, निवेशकों की रकम पर सवाल



नौकरी का भरोसा देकर निवेश कराते के भी आरोप-

मामले में यह आरोप भी लगाया गया है कि बेरोजगार युवाओं को कंपनी में 25 से 30 हजार रुपये मासिक वेतन पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया जाता था। शिकायतकर्ता का दावा है कि कंपनी के नाम और योजनाओं का हवाला देकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया। कंपनी के माध्यम से कथित तौर पर हजारों निवेशकों से बड़ी रकम जुटाए जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि, निवेशकों की वास्तविक संख्या और कुल राशि के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चिटफंड ग्रह के संचालक ने मोतीलाल ओसवाल ब्रांड दिखा कर निवेशकों को बनाया बेवकूफ-

वही SECL सेवानिवृत्त कालरी कर्मचारी इजहार बक्स निवास भालूमाड़ा ने पुलिस प्रशासन से लिखित शिकायत करते हुए चिटफंड कंपनी GNS financial services के संचालक सरोज यादव ,,सुखनंदन यादव,, मुकेश यादव,, निपेंद्र सिंह ब्रांच मैनेजर कोतमा निवासी भालूमाड़ा पर कम समय अवधि में अधिक मुनाफा का प्रलोभन देकर मोतीलाल ओसवाल बड़ी कम्पनी की बताकर पैसे जीएनएस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बुद्धार में निवेश कराकर कर पैसे की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पैसे मांगे पर आजकल पैसे देने की बात कह-कहा सात महीनों से इधर-उधर भटकने के लिए छोड़ दिया है। पोंडित इजहार बक्स ने पुलिस अधीक्षक

अनूपपुर से निवेश की गई राशि दिलाने और चिटफंड कंपनी के संचालकों,,स्थानीय ब्रांच मैनेजर कोतमा,, एवं एजेंटों के विरुद्ध निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

निवेशकों ने भी उठाई रकम वापसी की मांग-

गोविंद कॉलरी के वार्ड क्रमांक 12 निवासी मुस्तफा ने भी तहस के संचालकों एवं मैनेजरों के खिलाफ लगभग 20 से 22 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला कलेक्टर और कोतमा थाने में लिखित शिकायत देकर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है। यदि अलग-अलग शिकायतों में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो मामला कई निवेशकों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।

शील चंद जैन ने खोली ठगी की दुकान ,,ग्रह डिप्टी मैनेजर के खिलाफ पूर्व में धोखाधड़ी की शिकायत पर एफआईआर-

शिकायत में डिप्टी मैनेजर शील चंद जैन के खिलाफ पूर्व में भालूमाड़ा थाने में पैसे की धोखाधड़ी करने की शिकायत हुई थी।जानकारी के अनुसार, पोड़ी निवासी तेरसू केवट की शिकायत पर भालूमाड़ा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही गई है। इस संबंध में पुराने प्रकरण के दस्तावेजों और उसकी वर्तमान स्थिति की पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

खमरौध में अटल ग्राम सेवा सदन का लोकार्पण, 6 सड़कों का भूमिपूजन



जाने तथा ग्रामीणों को स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नवीन पंचायत भवन ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पंचायत स्तर की प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल बोले- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शासन की प्राथमिकता

विंध्य सत्ता,अनूपपुर। ग्राम खमरौध में शुक्रवार को कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल और शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने नवीन ग्राम पंचायत भवन अटल ग्राम सेवा सदन का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छह ग्रामीण सड़कों के निर्माण का भूमिपूजन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शासन की प्राथमिकता है। बेहतर शासक गांवों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल आने-

समस्याओं के निराकरण, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पंचायत स्तर की प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गांवों के सर्वांगीण विकास पर जोर

सांसद हिमाद्री सिंह ने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार शासन का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि अटल ग्राम सेवा सदन ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण और पात्र हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

अश्लील फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल कर युवती से दुष्कर्म का आरोप, 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, चर्चाई निवासी आरोपी न्यायालय में पेश, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जिला जेल

विंध्य सत्ता,अनूपपुर। युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली अनूपपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को 32 वर्षीय युवती ने थाना कोतवाली अनूपपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि चर्चाई निवासी सैम राजपूत उर्फ संजू ने उसके अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। मामले में थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 555/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता



को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर विक्रांत मुराब के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ सिंह मरकाम एवं एसडीओपी अनूपपुर के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय, महिला उपनिरीक्षक सरिता लकड़ा, प्रधान आरक्षक शेख रसीद, प्रधान आरक्षक प्रकाश तिवारी एवं आरक्षक अब्दुल कलीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोतवाली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया।

सीधी संसदीय क्षेत्र के 363 गांवों में विद्युतीकरण को मंजूरी, 14,085 घरों को मिलेगा लाभ

सीधी, सिंगरौली और ब्यूँहारी की बिजली से वंचित बस्तियों तक पहुंचेगी बिजली

विंध्य सत्ता,सिंगरौली/सीधी संसदीय क्षेत्र की बिजली से वंचित बस्तियों तक विद्युत सुविधा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। केंद्र सरकार की रियेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (ऋस्स) के तहत क्षेत्र के 363 गांवों की बस्तियों और मजरा में विद्युतीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इससे तीन क्षेत्रों के कुल 14,085 घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के अनुसार, इन बस्तियों तक बिजली पहुंचाने के लिए नवंबर 2025 से प्रयास किए जा रहे थे।

अब स्वीकृति मिलने के बाद लंबे समय से विद्युत सुविधा से वंचित परिवारों तक बिजली पहुंचाने का रास्ता साफ हुआ है।

सिंगरौली के 188 गांवों के 8,628 घर शामिल

स्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों में सिंगरौली जिले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। जिले के 188 गांवों के 8,628 घरों को योजना में शामिल किया गया है। वहीं, सीधी जिले के 123 गांवों के 3,444 घर और ब्यूँहारी विधानसभा क्षेत्र के 54 गांवों के 2,013 घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस



तरह कुल 363 गांवों के 14,085 घरों तक विद्युत सुविधा पहुंचाने की योजना है।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय विद्युत मंत्री के प्रति जताया आभार

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल तथा ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र की ऐसी बस्तियों तक बिजली पहुंचाना प्राथमिकता रही है, जहां अब तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

क्षेत्र के चहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित: विश्वामित्र पाठक

विंध्य सत्ता,सिंगरौली। सिहावल विधान सभा क्षेत्र में सड़क, बिजली,पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अधोसंरचना विकास सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य हो रहे हैं कोई भी क्षेत्र विकास से अधूरा नहीं रहेगा। सरकार क्षेत्र के चहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित है।उक्त आशय के विचार विश्वामित्र पाठक विधायक विधानसभा क्षेत्र सिहावल ने भितरी में गौशाला एवं दो पीसीसी मार्गों के लोकार्पण एवं दो पीसीसी मार्गों के भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर व्यक्त किए। विधानसभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत भितरी में नवनिर्मित गौशाला भवन एवं पीसीसी मार्गों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक श्री विश्वामित्र पाठक विधायक विधानसभा क्षेत्र सिहावल के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर एवं पट्टिका का अनावरण कर लोकार्पण एवं भूमि



पूजन किया। मां वीणावादिनी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई तत्पश्चात स्थानीय कलाकारों द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। राजेश शुक्ला एसडीएम ने लोकार्पण एवं भूमि पूजन किये जाने वाले निर्माण कार्यों की लागत एवं उपयोगिता से अवगत कराया तथा सेवा संकल्प अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने साराभित उद्बोधन में कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार ने अंतिम पवित्र के व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखकर अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की है आप लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पात्रतानुसार लाभ लेकर स्वयं के विकास के साथ साथ प्रदेश एवं देश के विकास में सहभागी बने।



मुख्य अतिथि ने कहा कि लंबे समय से प्रतिक्षित गौशाला का निर्माण हो जाने से किसानों की फसलों की सुरक्षा होगी वहीं बेसहारा पशुओं का संरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में पीसीसी मार्गों के निर्माण से आवागवन सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्य अतिथि ने कहा कि ग्राम वासियों द्वारा जिन विद्युत विहीन टोले मजरा में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग की गई थी उन सभी स्थानों पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जाएगा। मुख्य अतिथि ने ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना,सीधी सिंगरौली फोर लेन मार्ग निर्माण,गुलाब सागर नहर एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रगतिरत कार्यों के पूर्ण हो जाने से क्षेत्र

का सर्वांगीण विकास होगा। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर गौशाला भवन, भितरी स्कूल से बृहस्पति यादव बस्ती तक पीसीसी मार्ग निर्माण, छिरहा टोला से मलखम मार्ग तक पीसीसी मार्ग निर्माण एवं भितरी आंगनवाड़ी भवन से पडरिया सीमा तक पीसीसी मार्ग निर्माण का भूमि पूजन किया।मुख्य अतिथि ने वरिष्ठजनों व वृद्धजनों का शाल श्री फूल भेंट कर सम्मान भी किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्षपुष्पेंद्र पाण्डेय,जनपद सीईओ रोहित उपाध्याय,तहसीलदार हिमांशु शुक्ला, एसडीओ श्रेष्ण चतुर्वेदी ,अवधेश सिंह, योगेन्द्र नाथ पाठक,प्रमोद शर्मा, नीरज सिंह,दिलीप सोनी,सरपंच श्रीमती अनुपमा सिंह,उप सरपंच उर्मिला यादव, मोहन यादव,रितेश गुप्ता,पवन सिंह,हीरा लाल यादव, अशोक सिंह,रविराज सिंह,हीरा लाल साहू दिवाकर द्विवेदी ,लाल मणि कोल सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण जन उपस्थित रहे ।

ब्रह्माकुमारीज के तपोवन परिसर में सजी चैतन्य देवियों की मनोहारी झांकी



नवरात्रि पर मां दुर्गा सहित देवियों के अन्य स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे नगरवासी

विंध्य सत्ता,सिंगरौली। शारदेय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरिय विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय शाखा, ब्रह्माकुमारीज तपोवन कॉम्प्लेक्स, विंध्य नगर में चैतन्य देवियों की मनोहारी झांकी सजाई गई है। नवरात्रि के आध्यात्मिक एवं भक्तिमय वातावरण में सजी यह झांकी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस दिव्य झांकी में मां दुर्गा, मां गायत्री, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां उमा, मां संतोषी, मां मीनाक्षी एवं मां काली की चैतन्य प्रति मूर्तियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा।। देवियों के विभिन्न स्वरूपों को आकर्षक एवं आध्यात्मिक वातावरण में प्रस्तुत किया गया है, जो श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और देवी शक्तियों के दिव्य गुणों की अनुभूति कराते हैं। ब्रह्माकुमारीज के तपोवन परिसर में आयोजित इस झांकी का अवलोकन नगरवासी प्रतिदिन सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकते हैं। श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे अपने परिवार एवं इष्ट-मित्रों के साथ पधारकर चैतन्य देवियों के दर्शन का लाभ लें तथा आध्यात्मिक शांति, सुख एवं दिव्य अनुभूतियों से अपनी झोली भरपूर करें। यह आयोजन नवरात्रि के पावन पर्व



पर जनमानस में आध्यात्मिक चेतना जागृत करने तथा देवी स्वरूपों में निहित दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा देने का एक सुंदर माध्यम है।

खास खबर शासकीय भवनों की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश, अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

हाईकोर्ट के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय चितरंगी का निर्देश

विंध्य सत्ता,सिंगरौली/चितरंगी ग्राम पंचायत कर्थुआ की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला इन दिनों चर्चा में है। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में मिस पिटीशन क्रमांक 1239/2017 में पारित आदेश दिनांक 6 जनवरी 2023 के पालन में तहसील न्यायालय चितरंगी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0085/अ-68/2024-25 में 1 अक्टूबर 2026 को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है।



प्रकरण के अनुसार, ग्राम पंचायत कर्थुआ की शासकीय आराजी क्रमांक 500, 501 एवं 503 पर शासकीय भवन, बैगा भवन एवं ग्रामसेवक भवन निर्मित होने का उल्लेख किया गया है। संबंधित जानकारी के अनुसार, इन

सरपंच पद से जुड़ा मामला

इस प्रकरण को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है, क्योंकि अतिक्रमण के मामले में संबंधित व्यक्ति के वर्तमान में ग्राम पंचायत कर्थुआ के

सरपंच पद पर होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मुख्य सवाल यह है कि तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में प्रशासन मौके पर कब और किस तरह कार्रवाई करता है। शासकीय भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए जारी आदेश का क्रियान्वयन प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय है।

आदेश के पालन पर टिकी निगाहें

ग्राम कर्थुआ चौराहा बाजार में इस मामले को लेकर चर्चाएं जारी हैं। स्थानीय लोगों की निगाहें अब राजस्व विभाग और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कब तक पूरी होती है और शासकीय भूमि की स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।

करनपठार थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी की घटना, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम

विंध्य सत्ता,अनूपपुर। जिले के करनपठार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी में एक व्यक्ति का शव कुएं से बरामद किया गया। कुएं के पास जूते-चप्पल रखे होने और व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस तथा रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एवं होमगार्ड की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव परिजनों की मौजूदगी में पुलिस को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना करनपठार से शनिवार सुबह लगभग 7:10 बजे वायरलेस संदेश के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम देवरी निवासी रमेश सिंह लापता हैं। कुएं के पास उनके जूते-चप्पल रखे होने के कारण कुएं में डूबने की आशंका जताई गई। सूचना मिलने के बाद जिला सेनानी के निर्देश पर प्लाटून

कमांडर राम नरेश भवेदी के नेतृत्व में एसडीआरएफ एवं होमगार्ड के जवानों की टीम सुबह 7:30 बजे जिला मुख्यालय से घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर था।

10 मिनट में रेस्क्यू कर बाहर निकाला शव



रेस्क्यू टीम ने सुबह 9:25 बजे घटनास्थल पर बचाव कार्य शुरू किया और महज 10 मिनट के भीतर, सुबह 9:35 बजे, शव को कुएं से बाहर निकाल लिया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में शव पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। रेस्क्यू के दौरान मृतक के गले में पथर बंधा हुआ गमछ फंसे होने की बात भी सामने आई है। इस परिस्थिति को देखते हुए घटना के शनिवार सुबह लगभग 7:10 बजे वायरलेस संदेश के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम देवरी निवासी रमेश सिंह लापता हैं। कुएं के पास उनके जूते-चप्पल रखे होने के कारण कुएं में डूबने की आशंका जताई गई। सूचना मिलने के बाद जिला सेनानी के निर्देश पर प्लाटून

कारणों को लेकर जांच आवश्यक है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई। मृतक की पहचान रमेश सिंह, पिता लामू सिंह, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम देवरी, थाना करनपठार के रूप में हुई है।

सम्पादक की कलम से

सुखना अब ‘रामसर’

यह सुखद ही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ की सुखना झील के महत्व को स्वीकारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुखना वेटलैंड को ‘रामसर साइट’ का दर्जा मिलना चंडीगढ़ के लिये गर्व की बात है। लेकिन यह सम्मान मिलना हमारी जवाबदेही को भी बढ़ाना वाला भी है। साथ ही मानकीकरण, एक ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है- जो इसके तल पर गाद जमा होने,जल भंडारण क्षमता घटने तथा बढ़ते पर्यावरणीय दबावों के कारण हमारे सामने चुनौती पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाने वाला शहर का यह पहला वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि, केवल सरकारी उपलब्धि का प्रतीक मात्र बनकर नहीं रह जाना चाहिए। अब जरूरत इसकी मूल समस्याओं को दूर करने की होगी। उल्लेखनीय है कि यह ‘रामसर’ नाम इंगन के एक शहर के नाम से आया है, जहां इसे वर्ष 1971 में आर्द्रभूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में अपनाया गया था। निस्संदेह, सुखना केवल मनोरंजन का एक स्थान मात्र नहीं है। इसका पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य शिवालिक जलग्रहण क्षेत्र, आसपास के जंगलों और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर निर्भर करता है। इस व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए बिना केवल झील का संरक्षण करना एक अदृश्यी कसम होगा। यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाने से ही पारिस्थितिकीय अस्तित्व की गारंटी नहीं मिल जाती है। विगत में देश के अन्य भागों के अनुभव हमें एक चेतावनी देने का काम करते हैं। पूर्वी कोलकाता के वेटलैंड्स बढ़ती जनसंख्या के चलते अतिक्रमण और तेजी से विस्तार लेते शहरीकरण की समस्या का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर की तुलर झील का जल क्षेत्र सिमट रहा है। उसकी स्थिति समय के साथ खराब हुई है। कमोबेश ऐसी ही समस्या ओडिशा की चिल्का झील की भी है, जो गाद जमा होने की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन को आने वाले समय में सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये दूरगामी नीतियों का अनुपालन करना होगा। अब शासन-प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि सुखना झील की जल भंडारण क्षमता, इसके तल में गाद जमने से लगातार कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर जल स्तर में उतार-चढ़ाव और प्रदूषण का बढ़ना बताता है कि यहां निरंतर उपचारात्मक प्रयासों की जरूरत है। हम कभी-कभार गाद निकालने की कवायद करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। वास्तव में मिट्टी का संरक्षण, जल निकासी, चैनलों की सुरक्षा, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये एकीकृत रणनीति बनाने की जरूरत होगी। वहीं रामसर का दर्जा मिलने का यह मतलब कदापि नहीं है कि यहां निर्माण कार्य नहीं हो सकते, या इससे फैंडिज की गारंटी मिलती है। हमें यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि यह दर्जा मिलने से पारिस्थितिक नुकसान को रोका जा सकता है। निस्संदेह, प्रशासन को सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिये गंभीर प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही जैव विविधता और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये पहल करनी चाहिए। इसके अलावा संरक्षण योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करना चाहिए। ध्यान रहे कि सुखना झील का जलग्रहण क्षेत्र चंडीगढ़ के बाहरी इलाके तक फैला हुआ है। इसलिए पंजाब और हरियाणा के साथ समन्वय भी उतना ही जरूरी है। – **सम्पादक**

सवालों के घेरे में हैं ‘जेएनयू के क्रांतिकारियों’ की ‘चयनित चुप्पियां’

स्त्रियों ने इस समय में अपनी शक्ति को पहचान लिया है। वे बेहतर कर रही हैं और आगे आसमां छूने की कोशिशों में हैं। यहां भी पुरुष सत्ता चोटिल होती हुई लगती है। उसके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता के बजाए, किस्से बनाने और उसे कमतर साबित करने की कोशिशें हर स्तर हो रही हैं। शिक्षा केंद्रों की गुरु-शिष्य परंपरा को लजाते प्रकरण मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसी खबरें अब बहुत विचलित नहीं करतीं। किंतु बात जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा केंद्र की हो तो मामला साधारण नहीं रह जाता। आरोप किसी साधारण शिक्षक पर नहीं, मणिपुर से लोकसभा के सांसद प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर हैं। वे जेएनयू के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक थे। जेएनयू प्रशासन ने 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को बर्खास्त कर दिया है।

वे अभी सांसद बने हुए हैं। प्रो. बिमोल ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें सरकार विरोधी रवैये के कारण शिकार बनाया जा रहा है। इस सफाई के बहुत मायने नहीं हैं। मुद्दा है शिक्षक की गरिमा का, यदि वह जनप्रतिनिधि हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में जागरूक विद्यार्थियों की संख्या काफी है। राजनीतिक तौर पर भी उनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में किसी प्राध्यापक का यह रवैया आश्चर्यजनक है। उन छात्राओं के साहस को भी नमन करना चाहिए, जिनके कारण यह प्रकरण प्रकाश में आ सका। हमारी परंपरा में शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए अभिभावक हैं। इस गरिमा को छोड़कर अपने विद्यार्थियों का किसी भी तरह का शोषण स्वीकार्य नहीं है। यह उस अकादमिक भरोसे की हत्या है, जिस पर शिक्षा की नींव टिकी है। आरोपी प्रोफेसर के बारे में विश्वविद्यालय की आंतरिक

शिकायत समिति ने शिकायतों को सही पाया है। नैतिकता के आधार पर उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। यह बात रेखांकित करती है कि शिक्षा केंद्रों में शिक्षक सुरक्षित माहौल नहीं देगें तो युवा पीढ़ी का मानसिक और शैक्षणिक विकास कैसे होगा? यह भी सुखद है कि जागरूक विद्यार्थी अब किसी तरह के शोषण को सहने को तैयार नहीं हैं। पोंडिताएं अब डरने के बजाए संस्थानात प्रक्रियाओं का दरवाजा खटखटा रही हैं। स्त्रियों ने इस समय में अपनी शक्ति को पहचान लिया है। वे बेहतर कर रही हैं और आगे आसमां छूने की कोशिशों में हैं। यहां भी पुरुष सत्ता चोटिल होती हुई लगती है। उसके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता के बजाए, किस्से बनाने और उसे कमतर साबित करने की कोशिशें हर स्तर हो रही हैं। तेज होते सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के

इस दौर में सिर्फ कानून ही स्त्री के साथ खड़े हैं। कई जगह स्त्रियां भी, स्त्रियों के खिलाफ खड़ी हैं। यह संक्रमण काल है, स्त्री को अपने वजूद को साबित करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का समय है। वह जीत रही है और आगे बढ़ रही है। आज की बेटियां अपने सपनों में रंग भर रही हैं। आसान शिकार होने के नाते कुछ शिकारी उसकी घात में हैं, किंतु आज की औरत इससे डरती नहीं। घबराती नहीं। वह बने-बनाए कठघरों को तोड़कर आगे आ रही है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। आरोपी प्रोफेसर सांसद हैं तो उन्हें कुछ विशेषाधिकार जरूर हासिल हैं। ऐसे में मुद्दा यह भी है कि जब कानून बनाने वाले ही महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं तो राजनीतिक शुचिता का क्या होगा। दलगत राजनीति और चयनित चुप्पियों के समय में राजनीतक दलों का रवैया दोमुंहा हो जाता है।

लेखक- संजय द्विवेदी

दुनियाँ की अर्थव्यवस्था का अग्निपरीक्षा काल!

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के ऊर्जा बाजार में इन दिनों युद्ध, तेल की आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा का ऐसा त्रिकोण बन रहा है, जिसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर भी पड़ सकता है। एक ओर पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव, दूसरी ओर सऊदी अरब के हवाई अड्डों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की खबरें और तीसरी ओर भारत सरकार का पेट्रोल एवं डीजल निर्यात शुल्क में बदलाव,ये घटनाएं बताती हैं कि आज तेल केवल व्यापार की वस्तु नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर की देर रात जारी आदेश के माध्यम से 16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.50 रूपए से बढ़ाकर 2.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया, जबकि डीजल पर लगने वाला शुल्क 16 रूपए से घटाकर 8.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया। यानें पेट्रोल पर शुल्क बढ़ाकर पांच गुना हुआ, लेकिन डीजल पर 7.50 रूपए प्रति लीटर की कटौती हुई। सवाल है कि इस विरोधाभासी फैसले के पीछे क्या अर्थशास्त्र है, विंडफॉल टैक्स आखिर क्या है और क्या इससे आम

करना जरूरी है कि राष्ट्रपति भवन पर हमले की रिपोर्ट यमन के राष्ट्रपति परिसर से संबंधित है, न कि सऊदी अरब के राष्ट्रपति भवन से। वहीं, सऊदी अरब में हवाई अड्डों और सामरिक प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा तेल सुविधाओं को लेकर खतरे की खबरों ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं। इस संकट का



आर्थिक महत्व इसलिए अधिक है, क्योंकि सऊदी अरब वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। यदि तेल उत्पादन, रिफाइनरी संचालन, बंदरगाहों या समुद्री परिवहन में लंबे समय तक बाधा आती है, तो अंतरराष्ट्रीय समझने की करें तो, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर हमें चिंताएं पैदा कर दी हैं। यमन के हूती संगठन और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच तनाव बढ़ने के साथ मिसाइलों और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। 15 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, यमन के अदन स्थित अल-मआशिक राष्ट्रपति परिसर के आसपास भी हमला हुआ। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट

आपूर्ति और तेल भंडारों पर निर्भर करेगा।भारत के लिए यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा होने पर आयात बिल, रुपये की विनिमय दर, परिवहन लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।इसी पृष्ठभूमि में निर्यात

शुल्क की नीति को सटीकता से समझना आवश्यक है। साथियों बात अगर हम विंडफॉल टैक्स क्या है? आसान भाषा में समझने की करें तो,विंडफॉल टैक्स का सामान्य अर्थ है असाधारण परिस्थितियों में कंपनियों को होनेवाले अप्रत्याशित अतिरिक्त मुनाफेपर लगाया जाने वाला कर। उदाहरण के लिए, युद्ध या आपूर्ति संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ जाएं और किसी कंपनी को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ मिलने लगे, तो सरकार उस अतिरिक्त लाभ के एक हिस्से पर कर लगाने का निर्णय ले सकती है।लेकिन भारत के

मौजूदा मामले में तकनीकी अंतर समझना जरूरी है। पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लागू शुल्क को समाचारों में विंडफॉल टैक्स कहा जा रहा है, जबकि इसे विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा अन्य लागू उपकरणों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक कंपनी के वास्तविक अतिरिक्त मुनाफे की गणना करके ही प्रति लीटर शुल्क लगाया जाए। वर्तमान व्यवस्था में निर्यात पर निर्धारित दर लागू होती है। सरल उदाहरण से समझिए।यदि कोई रिफाइनरी नफा बाजार में बेचने के बजाय विदेश में पेट्रोल बेचकर अधिक कमाई कर सकती है, तो सरकार निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर उस विकल्प को कुछ महंगा बना सकती है। इससे घरेलू विक्री और निर्यात के बीच आर्थिक संतुलनप्रभावित हो सकता है। हालांकि, केवल शुल्क बढ़ाने से कंपनियां अनिवार्य रूप से सारा ईंधन घरेलू बाजार में बेचेंगी,इसकी गारंटी नहीं होती; इसके लिए मांग, उत्पादन क्षमता, निर्यात अनुबंध और अन्य नियम भी महत्वपूर्ण हैं। साथियों बात अगर हम 16 अक्टूबर से लागू नई दरों को समझने की करें तो पेट्रोल पर पांच गुना बढ़ावती, डीजल पर कटौती, केंद्र सरकार के नए आदेश के अनुसार पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में अलग-अलग बदलाव किए गए हैं। विवरण पुरानी दर नई दरपेट्रोल निर्यात शुल्क 0.50 रूपए /लीटर 2.50/रूपए लीटर डीजल निर्यात शुल्क 16/रूपए लीटर 8.50 रूपए / लीटर डीजल शुल्क में कमी - 7.50रूपए /लीटर इसका अर्थ है कि पेट्रोल पर शुल्क में २2 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल पर ७7.50 प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसलिए इसे केवल कर कीमतें तेजी से बढ़ जाएं और किसी कंपनी को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ मिलने लगे, तो सरकार उस अतिरिक्त लाभ के एक हिस्से पर कर लगाने का निर्णय ले सकती है।लेकिन भारत के

शुल्क घटने से उसके निर्यात पर पड़ने वाला कर-भार कम होगा। सरकार के आदेश में दोनों दरों में बदलाव किया गया है, लेकिन केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सरकार ने पेट्रोल की घरेलू कमी की पुष्टि कर दी है या डीजल की आपूर्ति सटीकता से पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। साथियों बात अगर हम सरकारी विंडफॉल टैक्स क्यों लगाती है? तीन प्रमुख उद्देश्य को समझने की करें तो पहला उद्देश्य है घरेलू ऊर्जा सुरक्षा। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत आकर्षक हों, तो कंपनियों के लिए निर्यात करना अधिक लाभकारी हो सकता है। निर्यात शुल्क इस लाभ को प्रभावित करके घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के सरकारी प्रयास का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, आपूर्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।दूसरा उद्देश्य है सरकारी राजस्व और सार्वजनिक खर्च। अतिरिक्त शुल्क से मांग, उत्पादन क्षमता, निर्यात अनुबंध और अन्य नियम भी महत्वपूर्ण हैं। साथियों बात अगर हम 16 अक्टूबर से लागू नई दरों को समझने की करें तो पेट्रोल पर पांच गुना बढ़ावती, डीजल पर कटौती, केंद्र सरकार के नए आदेश के अनुसार पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में अलग-अलग बदलाव किए गए हैं। विवरण पुरानी दर नई दरपेट्रोल निर्यात शुल्क 0.50 रूपए /लीटर 2.50/रूपए लीटर डीजल निर्यात शुल्क 16/रूपए लीटर 8.50 रूपए / लीटर डीजल शुल्क में कमी - 7.50रूपए /लीटर इसका अर्थ है कि पेट्रोल पर शुल्क में २2 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल पर ७7.50 प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसलिए इसे केवल कर कीमतें तेजी से बढ़ जाएं और किसी कंपनी को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ मिलने लगे, तो सरकार उस अतिरिक्त लाभ के एक हिस्से पर कर लगाने का निर्णय ले सकती है।लेकिन भारत के

लेखक- एडवोकेट किशन



आस्था

आश्विन माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन रविवार

ऑनलाइन मेडिकल पाठ्यक्रम: वैज्ञानिक साक्ष्यों की त्याख्या में आत्मविश्वास का मार्ग

चिकित्सा विज्ञान असाधारण गति से आगे बढ़ रहा है। नई उपचार पद्धतियाँ, निदान तकनीकें, दवाइयों और चिकित्सकीय दिशा-निर्देश लगातार विकसित हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों के लिए नवीनतम वैज्ञानिक साक्ष्यों से अवगत रहना आवश्यक हो गया है। लेकिन केवल चिकित्सा संबंधी जानकारी प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टरों, मेडिकल विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना तथा विश्वसनीय निष्कर्षों और भ्रामक दावों के बीच अंतर करना भी सीखना चाहिए। ऑनलाइन मेडिकल पाठ्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ इसकी लचीलापन है। चिकित्सा पेशेवरों की व्यस्त दिनचर्या के कारण पारंपरिक कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेना कठिन हो सकता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम उन्हें अपनी सुविधाानुसार अध्ययन करने, जटिल विषयों को दोबारा समझने और विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों की शैक्षिक सामग्री तक पहुँचने का अवसर देते हैं। साथ-आधारित चिकित्सा, जैव-सांख्यिकी, शोध पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययनों के आलोचनात्मक मूल्यांकन और व्यवस्थित समीक्षा जैसे विषय अब भौगोलिक सीमाओं से परे उपलब्ध हैं।

व्यावस्थित समीक्षा किसी विशिष्ट प्रश्न से संबंधित शोध अध्ययनों की पहचान, मूल्यांकन और उनके निष्कर्षों के समेकन की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सामान्य सहित्य समीक्षा के विपरीत, इसमें पूर्वनिर्धारित पद्धति अपनाई जाती है, जिससे पक्षपात की संभावना कम होती है और निष्कर्षों में पारदर्शिता बढ़ती है। उपयुक्त परिस्थितियों में



पद्धतियाँ निष्कर्षों को प्रभावित कर सकती हैं। उपलब्ध शोध साक्ष्यों का सामूहिक विश्लेषण करके व्यवस्थित समीक्षा चिकित्सा पेशेवरों को किसी विषय की व्यापक समझ विकसित करने में सहायता करती है। हालाँकि, केवल व्यवस्थित समीक्षा कहलाने से कोई अध्ययन स्वतः विश्वसनीय नहीं हो जाता। उसकी गुणवत्ता अपनाई गई पद्धति, शामिल किए गए अध्ययनों की प्रासंगिकता और उपलब्ध साक्ष्यों की सीमाओं पर निर्भर करती है। इसलिए व्यवस्थित समीक्षाओं की सही और आलोचनात्मक व्याख्या करना एक आवश्यक व्यावसायिक कौशल है। तप्त

प्रकार तैयार और परखे जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी स्पष्ट चिकित्सकीय प्रश्न तैयार करना, उपयुक्त शोध अध्ययनों की पहचान करना, पक्षपात के कारणों का आकलन करना और सांख्यिकीय परिणामों की व्याख्या करना सीख सकते हैं। वे विश्वास अंतराल , सापेक्ष एवं निरपेक्ष जोखिम, अध्ययनों के परिणामों में विषमता तथा प्रकाशन पक्षपात जैसी अवधारणाओं को भी समझ सकते हैं। शुरुआती विद्यार्थियों के लिए ये विषय कठिन हो सकते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास और सरल शिक्षण सामग्री से इन्हें समझना आसान हो जाता है।

ऑनलाइन शिक्षा स्वतंत्र और तार्किक सोच को भी प्रोत्साहित करती है। शोध के किसी निष्कर्ष को बिना जाँच स्वीकार करने के बजाय विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या अध्ययन की रूपरेखा उचित थी? क्या प्रतिभागी लक्षित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे? क्या परिणाम चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण थे? क्या अध्ययन की सीमाओं का उल्लेख किया गया था? क्या किसी प्रकार के पक्षपात ने निष्कर्षों को प्रभावित किया हो सकता है? जब ऐसे प्रश्न वैज्ञानिक सोच का हिस्सा बन जाते हैं, तो शोध निष्कर्षों का मूल्यांकन करने में आत्मविश्वास बढ़ता है। चिकित्सा अनुसंधान की व्याख्या में एक बड़ी चुनौती सांख्यिकीय महत्त्व और चिकित्सकीय महत्त्व के बीच अंतर समझना है। कोई परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे रोगी के स्वास्थ्य में व्यावहारिक रूप से बड़ा फायदा होगा या नहीं, यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, किसी छोटे अध्ययन में उपचार लाभकारी दिखाई दे सकता है, जबकि उसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा की पुष्टि के लिए बड़े तथा बेहतर शोध अध्ययनों की आवश्यकता हो सकती है। साथ-आधारित चिकित्सा के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रभाव के आकार, विश्वास अंतराल, निरपेक्ष जोखिम में कमी और आवश्यक उपचार संख्या जैसी अवधारणाओं को समझने में सहायता करते हैं। इनसे उपचार के संभावित लाभों और हानियों का संतुलित मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी दवा के बारे में कहा जा सकता है कि वह किसी बीमारी के सापेक्ष जोखिम को 50 प्रतिशत कम करती है। लेकिन यदि प्रारंभिक जोखिम

प्रति 1,000 लोगों में केवल दो मामलों का था, तो उपचार के बाद यह घटकर प्रति 1,000 लोगों में एक मामला रह जाएगा। इस प्रकार सापेक्ष जोखिम में 50 प्रतिशत की कमी के बावजूद निरपेक्ष कमी प्रति 1,000 लोगों में केवल एक मामला है। इस अंतर को समझने से चिकित्सक रोगियों को उपचार के वास्तविक लाभों की अधिक सटीक जानकारी दे सकते हैं और बेहतर निर्णय लेने में उनकी सहायता कर सकते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्यों की व्याख्या में आत्मविश्वास का अर्थ शोध निष्कर्षों को बिना प्रश्न किए स्वीकार करना नहीं है। व्यवस्थित समीक्षाएँ भी कमजोर गुणवत्ता वाले अध्ययनों, अधूरी जानकारी, चुनिंदा प्रकाशन और शामिल अध्ययनों के बीच अत्यधिक अंतर के कारण सीमित हो सकती हैं। विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इनमें शोध पद्धति की गुणवत्ता, परिणामों की संगति, अनुमानों की सटीकता और चिकित्सकीय प्रश्न के संदर्भ में साक्ष्य की प्रासंगिकता शामिल हैं। उन्हें विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव और किसी उपचार के अप्रभावी होने के ठोस प्रमाण के बीच अंतर भी समझना चाहिए। दोनों स्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं। शोध-पत्रों के आलोचनात्मक मूल्यांकन, मान्यता प्राप्त मूल्यांकन उपकरणों और रिपोर्टिंग दिशा-निर्देशों के व्यावहारिक प्रशिक्षण से इन सीमाओं की पहचान करना आसान हो सकता है। यह कौशल आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब स्वास्थ्य संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट, शोध-सारांश और कुंठित बुद्धिमत्ता से तैयार उत्तर व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।

लेखक – डॉ विजय गर्ग

महिला खिलाड़ियों के लिए बने मजबूत खेल नीति

हालिया एशियाई खेलों में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन दमदार रहा जो उनके मजबूत इरादों और सामाजिक समर्थन का सबूत कहा जाएगा। इस दिशा में परिणाम और बेहतर हों इसके लिए महिला-केंद्रित खेल नीति चाहिए। वहीं देहात में खेल सुविधाएं बढ़ाने और लोकप्रिय खेल-संस्कृति के विकास की जरूरत है। जापान के आयाची नागोया में हाल ही में संपन्न हुए बीसवें एशियाई खेलों में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों द्वारा जीते गए ढेर सारे मेडल प्रमाण हैं कि पिछले दिनों खेल जगत में सामने आई संस्थागत यौन शोषण की घटनाओं के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। यह इसलिए संभव हो पाया कि प्रदेश की सविल सोसायटी अपनी बेटियों के न्याय के संघर्ष में साथ खड़ी रही। चाहे वह कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभक्त समझ रहे हों या प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का, या फिर सिरटम का रवैया। गर्व व खुशी का विषय है कि हमने बेटियों के खेल कैरियर को प्रतिक्रियावादी ताकतों की बलि नहीं चढ़ने दिया। उल्लेखनीय है कि 2026 एशियाई खेलों में हरियाणा ने कुल 32 पदकों का योगदान किया, जिनमें 14 स्वर्ण, 9 रजत तथा 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इन 14 स्वर्ण में से 8 सिर्फ महिलाओं ने जीते, जिनमें दो व्यक्तिगत तथा 6 टीम गेम में जीते गए। यह सराहनीय उपलब्धि है। गौर करने लायक है कि हरियाणा की बेटियों की प्रतिभा-प्रदर्शन का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। अब वे केवल कुश्ती, बॉक्सिंग या कबड्डी आदि ताकत-आधारित खेलों में ही जीत हासिल नहीं कर रही हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता, एकाग्रता, प्रतिक्रिया नियंत्रण, सटीकता आदि की जरूरत वाले खेलों, जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, स्केट्स, एमएमए, गोल्फ और क्रिकेट में भी धाक जमा रही हैं। इसका अर्थ है कि अब 'बेटियों को मजबूत बनाओ, खेल-कूद में आगे लाओ' आदि महिला आंदोलन द्वारा गढ़े गए नारों का भीमवक समझ रहे हैं। वहीं अब केंद्र सरकार के नारे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ' की चरितार्थ करने की जरूरत है। इन नारों को चरितार्थ करने का मतलब है कि एक महिला खेल नीति बनाई जाए, जिसका सरोकार महिला खिलाड़ियों के आसपास विभिन्न स्तरीय खेल सुविधाओं का निर्माण करना हो। क्योंकि खेल लड़कियों के जीवन में मनोरंजनकारी व स्वास्थ्यवर्धन की गतिविधि ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास-वर्धन की गतिविधि भी है। आजकल मेडल विजेता युवतियों को जो सम्मान दिया जाता है, उससे राज्य के गिरे तलांगपुता पर भी अंकुरा लगाने में मदद मिलेगी। महिला खेल गतिविधियों पर ज्यादा बजट लगाने की जरूरत है। खेल के मैदान, कौचिंग सुविधा और खेल का सामान पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि जिस क्षेत्र में जिस खेल की ज्यादा प्रतिभा नजर आए, उस पर अवश्य ध्यान दिया जाए।

लेखक- डॉ. जगमती सांगवान



सेवा संकल्प अभियान 2026: सेवा की कहानी

ब्रॉड बेड पद्धति अपनाकर कृषक अनुकूल सिंह ठाकुर ने प्राप्त किया बेहतर उत्पादन

खंड स्तरीय शिविर में साझा किए
आधुनिक कृषि तकनीक के
सकारात्मक परिणाम

अनुराग विश्वकर्मा जिला ब्यूरो

विंध्य सत्ता,सागर /सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत 'कहानी सेवा की' श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित खंड स्तरीय शिविर में ग्राम तेवरा के उन्नतशील कृषक श्री अनुकूल सिंह ठाकुर ने कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने से मिले सकारात्मक परिणामों के अनुभव साझा किए। कृषक श्री ठाकुर ने बताया कि कृषि विभाग के माध्यम से उन्हें सोयाबीन की खेती में ब्रॉड बेड



(चौड़ी क्यारी) पद्धति से बुवाई करने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उन्होंने विभागीय सलाह के अनुसार इस तकनीक से सोयाबीन की बुवाई की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पारंपरिक बुवाई पद्धति की तुलना में बेहतर उत्पादन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। श्री ठाकुर ने अन्य किसानों से भी अपील की कि वे कृषि विभाग के अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर अनुशंसित कृषि तकनीकों को अपनाएं और खेती में नवाचार के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त करें। यह पहल कृषक कल्याण की दिशा में कृषि विभाग के प्रयासों तथा किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकों का लाभ पहुंचाने का सकारात्मक उदाहरण है।

हार्दिक आनंद ने बेंगलोर से लॉ आनर्स की उपाधि प्राप्त की



अनुराग विश्वकर्मा जिला ब्यूरो

विंध्य सत्ता,सागर /नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के 34 वे दीक्षांत समारोह में सागर लोकसभा के पूर्व सांसद डॉ आनंद अहिरवार के पुत्र हार्दिक आनंद को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, श्री सूर्य कान्त एवं माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक, श्री डी. के. शिवकुमार के कर कमलों से रूझ (Hons) डिग्री प्राप्त की। इस अवसर पर हार्दिक आनंद को सम्मस्त परिजनों मित्रगणों आत्मीय जनों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

सेवा संकल्प अभियान का मत्स्य समापन

अनुराग विश्वकर्मा जिला ब्यूरो

विंध्य सत्ता,सागर / खिमलासा, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय खिमलासा में प्राचार्य डॉ. पूर्वा सांगलीकर के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित सेवा संकल्प अभियान का शनिवार को भव्य समापन हुआ। इस अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम प्रभारी श्री सत्येन्द्र कुमार आठिया द्वारा आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों में सेवा भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता एवं राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न रचनात्मक एवं जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। एक माह तक चले इस अभियान में प्रमुख रूप से 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता, 'सेवा मेरा योगदान' के अंतर्गत श्रमदान एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सेवा सेतु योजना जागरूकता अभियान, 'कहानी बदलाव की' के अंतर्गत सफलता कथाओं का संकलन, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' पर नुक्कड़ नाटक, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण, स्वास्थ्य, पोषण एवं महिला स्वच्छता जागरूकता, नशा मुक्त भारत अभियान, कैरियर काउंसिलिंग, फिट इंडिया एवं मतदान जागरूकता तथा



'नमो सेवा : अनकही कहानी' का मंचन किया गया। छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. प्रतिभा राज ने कहा कि ऐसे रचनात्मक एवं सेवा आधारित कार्यक्रम विद्यार्थियों में नई ऊर्जा, उत्साह एवं सकारात्मक सोच का संचार करते हैं और उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. एल.एन. दुबे ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान विद्यार्थियों में अनुशासन, सहयोग एवं नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी तरुण दीक्षित, डॉ. शाहबाज सुन्नी, डॉ. रफी अहमद, डॉ. अशोक यादव, चंद्रभान साकेत, डॉ. शुभम विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, डॉ. रूपाली जैन, डॉ. वंदना मीणा, डॉ. शुभो जैन, डॉ. दिनेंद्र, डॉ. प्रदीप अतुलकर, पुष्पेंद्र अहिरवार, दामोदर पटेल सहित समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में

जयकारों से गूंज उठा मां का दरबार, दुर्गा उत्सव में उमड़ रहे श्रद्धालु



नवयुवक दुर्गा उत्सव कमेटी एवं महादेव गणेश उत्सव कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं का स्वागत

जिला ब्यूरो दीपक बढेलिया मैहर

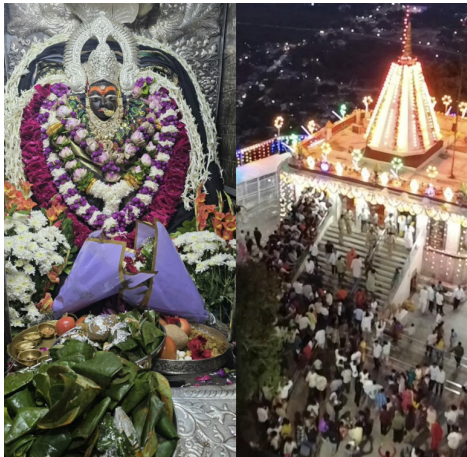
विंध्य सत्ता मैहर। मां शारदा की पावन नगरी मैहर में धार्मिक आस्था और भक्ति का माहौल बना हुआ है। नगर के चौरसिया मोहल्ला, बजरंग अखाड़ा क्षेत्र में नवयुवक दुर्गा उत्सव कमेटी एवं महादेव गणेश उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित धार्मिक उत्सव के दौरान मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु पूरे

उत्साह और श्रद्धा के साथ माता रानी के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। उत्सव के दौरान मां के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं में दर्शन और पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक आयोजन के माध्यम से क्षेत्र में भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का संदेश दिया जा रहा है।

श्रद्धालुओं का किया स्वागत

नवयुवक दुर्गा उत्सव कमेटी एवं महादेव गणेश उत्सव कमेटी, चौरसिया मोहल्ला, बजरंग अखाड़ा, मैहर की ओर से समस्त श्रद्धालुओं का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन किया गया। कमेटी ने श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजनों में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। मां के जयकारों और भक्तिमय वातावरण के बीच क्षेत्र में उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। श्रद्धालु मां दुर्गा एवं भगवान श्री गणेश से सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं।

कलेक्टर श्रीमती मुखर्जी और पुलिस अधीक्षक श्री सिंह के नेतृत्व में माँ शारदा मंदिर में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की आवश्यक व्यवस्थायें



शारदेय नवरात्र में मां शारदा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब सप्तमी तक 6.91 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन

दर्शन किए।मंदिर के गर्भगृह के पट शनिवार तड़के सुबह 3 बजे खोले गए। इसके पूर्व प्रधान पुजारी श्री पवन पांडे द्वारा विधि-विधान से मां शारदा का अभिषेक, श्रृंगार एवं पूजन संपन्न कराया गया। पूजन के उपरांत श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए।शारदेय नवरात्र के प्रथम दिन से सप्तमी तक 6 लाख 91 हजार से अधिक श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती विदिशा मुखर्जी और पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था, विश्राम स्थलों एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीढ़ी मार्ग, सड़क वाहन मार्ग एवं रोपवे के माध्यम से दर्शनार्थी मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वृद्ध, दिव्यांग दर्शनार्थियों के लिए विशेष रूप से दर्शन व्यवस्था की गई है,ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

डिप्टी कलेक्टर सुश्री मोना दांगी को मालथौन एसडीएम का दायित्व सौंपा

अनुराग विश्वकर्मा जिला ब्यूरो

विंध्य सत्ता,सागर / कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सुश्री मोना दांगी, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय सौंपा गया है।

अधिकारी (राजस्व) मालथौन के पद पर पदस्थ किया है। जारी आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मोना दांगी की शाखाओं का संपूर्ण प्रभार संयुक्त कलेक्टर श्री रवीश श्रीवास्तव को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से

मैहर स्वतंत्रने मददगार! घायल भाई -बहन को पहुंचाया अस्पताल

जिला ब्यूरो दीपक बढेलिया मैहर

विंध्य सत्ता मैहर। मैहर सड़क हादसे के बाद घायल भाई-बहन के लिए मैहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने अपने वाहन से सविल अस्पताल मैहर पहुंचाया। बंशीपुर निवासी सौरभ पाल (16 वर्ष) और उनकी बहन शिवानी पाल (लगभग 18 वर्ष) मोटरसाइकिल से बंशीपुर से मैहर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से ट्रक आने पर उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दोनों घायल हो गए थे।

01 वर्ष पुरानी चोरी का खुलासा सून मकान में चोरी करने वाले आरोपी को थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, नगदी एवं चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद



जिला ब्यूरो दीपक बढेलिया मैहर

मकान में दिनांक 31.08.2025 की रात्रि अज्ञात चोर द्वारा घर के अंदर प्रवेश कर कमरों एवं अलमारियों के ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, पीतल-कांसा के बर्तन एवं ₹20,000 नाद चोरी कर लिए गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ताला में अपराध क्रमांक 227/25 धारा 331(4), 305(क) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में थाना ताला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए संदेही राजमणि

उर्फ संतलाल केवट पिता जयकरण उर्फ मेम्मा केवट उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम ललितपुर नं. 02, थाना ताला, जिला मैहर जो पूर्व में कई चोरी की घटनाएं घटित कर जेल जा चुका है जिससे संदेह के आधार पर पृष्ठताछ की गई। पृष्ठताछ के दौरान आरोपी द्वारा उक्त चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से 7,200/- नाद एवं चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार आरोपी- राजमणि उर्फ संतलाल केवट पिता जयकरण उर्फ मेम्मा केवट उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम ललितपुर नं. 02 थाना ताला जिला मैहर (म.प्र.) जसी- 7,200/- नाद एवं चोरी में प्रयुक्त औजार कटार पाना पेचकस. प्लास एवं अन्य इत्यादि सुराहनीय भूमिका- निरी. महेंद्र कुमार मिश्रा थाना प्रभारी ताला, सजनि. रामनरेश मिश्रा, प्र.आर. राकेश मिश्रा, प्र.आर. पंकज मिश्रा, प्र.आर. चंदन शुक्ला, प्र.आर. इच्छालाल तिवारी, आर. आशीष मिश्रा, आर. विवेक मिश्रा आर. शम्भू प्रसाद राय, आर. संतोष द्विवेदी, सै. कमलेन्द्र सिंह।

खास खबर मैहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश गौतम भारत सरकार के केंद्रीय नोटरी नियुक्त विधिक क्षेत्र में मिली महत्वपूर्ण उपलब्धि, अधिवक्ता जगत एवं शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल

जिला ब्यूरो दीपक बढेलिया मैहर

विंध्य सत्ता मैहर। मैहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश गौतम को भारत सरकार के विधि विभाग, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय नोटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति को मैहर के विधिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नियुक्ति की खबर से अधिवक्ता जगत, मित्रों, शुभचिंतकों एवं आम जनमानस में हर्ष व्याप्त है। अधिवक्ता राजेश गौतम लंबे समय से मैहर में विधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे



राजेश गौतम पूर्व में महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष एवं भारतीय

जनता युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष सहित विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। विधिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय नोटरी के पद पर उनकी नियुक्ति को उनके विधिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय नोटरी के रूप में वे निर्धारित वैधानिक प्रावधानों एवं अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत नोटरी संबंधी कार्यों का संपादन करेंगे। यह नियुक्ति

उनके व्यावसायिक दायित्वों के विस्तार के साथ ही मैहर के विधिक क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है।

नियुक्ति पर मिल रही बधायाँ

अधिवक्ता राजेश गौतम की इस उपलब्धि पर अधिवक्ताओं, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों, मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। सभी ने आशा व्यक्त की है कि वे अपने नए दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं विधिक मर्यादाओं के अनुरूप करते हुए समाज को अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे।

‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारों से गूंजा मैहर, कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली, स्टूडेंट चौराहे पर किया पुतला दहन



मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन

जिला ब्यूरो दीपक बढेलिया मैहर

विंध्य सत्ता मैहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैहर के संयुक्त तत्वावधान में बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'वोट चोरो गद्दी छोड़ो' और 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान

बचाओ' के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट चौराहे पर पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। बाइक रैली कटनी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ होकर बाबा अलाउद्दीन खान चौराहा, महाकाल स्कूल, किला चौक, रहीम चौराहा, रंगलाल चौराहा, चौरसिया मोहल्ला, घंटाघर एवं स्टेट बैंक चौराहा सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। रैली के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के मतधिकार की रक्षा सर्वोपरि है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का उचित समाधान होना चाहिए तथा पूरे मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ब्लैक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव और मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। जनता के वोट की ताकत का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

धर्म और जनजागरण का संगम बनी चुनरी यात्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव हुए शामिल

खेड़ापति माता मंदिर से मां हिंगलाज मंदिर तक निकली यात्रा, नशामुक्त भारत का दिया संदेश

विंध्य सत्ता,छिंदवाड़ा। धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश लेकर मानकादेही खुर्द में भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। खेड़ापति माता मंदिर से मां हिंगलाज मंदिर तक निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जनपद सदस्य कुबेर सिंह सूर्यवंशी एवं उनके मित्र मंडल द्वारा आयोजित यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव भी शामिल हुए। यात्रा के माध्यम से नशामुक्त भारत के निर्माण और युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मां हिंगलाज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और देश-प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की



कामना की। धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक सरोकारों को जोड़ते हुए आयोजकों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प भी दोहराया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-

साथ उसके परिवार और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। नशामुक्त भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और स्वयं नशे से दूर रहने के साथ दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करे। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से जनजागरण का संदेश व्यापक स्तर

तक पहुंचाया जा सकता है। नशे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवार, समाज और युवाओं की सहभागिता जरूरी है। स्वस्थ परिवार और जागरूक नागरिक ही एक सशक्त समाज की नींव रखते हैं। चुनरी यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। आयोजकों ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों से आगे आने और अपने आसपास जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर धर्मेन्द्र मिगलानी, गोपाल यदुवंशी, जुगल यादव, अनीश पटेल सहित अनेक धर्मप्रेमी उपस्थित रहे।

सांदीपनि विद्यालय में 401 कन्याओं का पूजन, कन्याभोज के साथ बांटी शिक्षण सामग्री



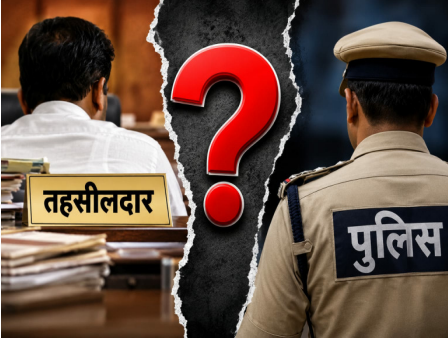
कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ और एसपी विदिता डायर ने किया कन्याओं का पूजन, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति किया प्रोत्साहित विंध्य सत्ता,पांडुर्णा । नवरात्रि के पावन अवसर पर शासकीय सांदीपनि विद्यालय, पांडुर्णा के प्राथमिक विभाग में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक विदिता डायर ने विधि-विधान से 401

कन्याओं का पूजन किया। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराया गया और उन्हें शिक्षण सामग्री वितरित की गई। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालिकाओं की सहभागिता रही। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन की परंपरा के अनुरूप बालिकाओं का सम्मान किया गया। एक साथ 401 कन्याओं के पूजन और कन्याभोज के आयोजन ने कार्यक्रम को विशेष स्वरूप दिया। अतिथियों ने विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए इस परंपरा को आगे भी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षण सामग्री के वितरण का उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना रहा। इस तरह धार्मिक परंपरा के साथ बालिकाओं के सम्मान और शिक्षा के महत्व को भी प्रमुखता दी गई।

मयूरवन के 6 जुआरियों में चार को जेल, दो को जमानत एक ही मामले में अलग-अलग कार्रवाई, जमानत मिलने के आधार पर उठे सवाल

भुवन लाल सिंह कुशवाहा बाबा जिला ब्यूरो, छिंदवाड़ा

विंध्य सत्ता,परासिया। मयूरवन के बंधा मोहल्ला क्षेत्र में खुले जंगल में संचालित जुए के फंड पर परासिया पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अब एक नए सवाल को जन्म दे रही है। पुलिस ने जुआ खेलते हुए छह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। एसडीएम की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई तहसीलदार परासिया द्वारा की गई। इसके बाद चार लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि दो लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सभी छह लोगों के विरुद्ध एक ही मामले में कार्रवाई की गई थी, तो आखिर किन आधारों पर चार लोगों को जेल भेजा गया और दो लोगों को रहत दे दी गई?प्रास जानकारों के अनुसार, मयूरवन के बंधा मोहल्ला क्षेत्र में जुआ खेलते जाने की सूचना पर परासिया पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने के आरोप में छह लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जुआ एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद न्यायालय में हुई कार्यवाही ने पूरे घटनाक्रम को चर्चा का विषय बना दिया है। छह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होने के बावजूद चार को जेल भेजा गया, जबकि दो को जमानत मिल गई।



घूमने जाने की बात कहकर मिली राहत

तहसील न्यायालय में पेश किए गए छह लोगों में से दो को जमानत मिलने के संबंध में जब तहसीलदार परासिया से चर्चा की गई, तो कथनों के आधार पर निर्णय लिया जाने की बात सामने आई। बताया गया कि कथनों में दो व्यक्तियों के घूमने जाने की बात कही गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केवल दो व्यक्तियों के कथनों के आधार पर उन्हें राहत दी गई? यदि अन्य चार व्यक्ति भी यह दावा करते हैं कि वे वहां घूमने गए थे, तो उनके संबंध में क्या विचार किया गया? क्या पुलिस की जांच में सभी छह लोगों की भूमिका समान पाई गई थी या उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों में कोई अंतर था?इन सवालों का स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है, ताकि यह समझा जा सके कि छह लोगों के मामले में अलग-अलग निर्णय लेने का आधार क्या रहा।

एक ही मामले में चार जेल और दो को जमानत, आखिर क्यों

कानून के तहत किसी भी मामले में जमानत देने या न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर लिया जाता है। इसलिए केवल एक ही मामले में शामिल होने से सभी आरोपियों के साथ एक जैसा निर्णय होना अनिवार्य नहीं माना जा सकता। हालांकि, अलग-अलग निर्णय के पीछे उचित कानूनी आधार होना चाहिए।ऐसे में इस प्रकरण में भी यह जानना जरूरी है कि चार लोगों को जेल भेजने और दो को जमानत देने के पीछे क्या कारण रहे। क्या दोनों व्यक्तियों के संबंध में कोई अलग तथ्य सामने आया था? क्या उनके कथनों या अन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी भूमिका अलग पाई गई थी? अथवा कोई अन्य कानूनी आधार था?इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित आदेश और मामले के अभिलेखों से ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी पक्ष की कार्रवाई गलत थी, लेकिन निर्णय के आधार को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है।

जंगल में जुए के फंड पर दबिश देना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण

खुले जंगल और सुनसान इलाकों में संचालित जुए के फंड पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए आसान नहीं होता। ऐसे स्थानों पर पहुंचने के लिए पुलिस को कई बार घेराबंदी करनी पड़ती है। आरोपियों के भागने की आशंका और घटनास्थल की परिस्थितियों के बीच कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

पहली किशत मिलने के आठ माह बाद भी मकान नहीं बनाए, 232 हितग्राहियों को निगम का नोटिस निर्माण शुरू नहीं किया तो निरस्त होंगे प्रकरण, एक लाख रुपये की होगी वसूली

विंध्य सत्ता,छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए पहली किशत की राशि मिलने के बावजूद मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों पर नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने सख्ती शुरू कर दी है। वर्ष 2025 में स्वीकृत प्रथम और द्वितीय डीपीआर के ऐसे 232 हितग्राहियों को निगम ने नोटिस जारी किया है, जिन्हें आठ माह पहले पहली किशत की राशि मिल चुकी है, लेकिन अब तक उन्होंने आवास निर्माण का काम शुरू नहीं किया है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर निगम प्रशासन ने जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है। निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर जारी नोटिस में संबंधित हितग्राहियों को तत्काल आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर निगम प्रशासन ने जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है। निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर जारी नोटिस में संबंधित हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।



होगी स्वीकृति

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के बाद भी यदि संबंधित हितग्राही निर्धारित नियमों के अनुसार अपने भूखंड पर आवास निर्माण शुरू नहीं करते हैं, तो उनके स्वीकृत प्रकरण निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही शासन की ओर से पहली किशत के रूप में दी गई एक लाख रुपये की राशि भी वापस वसूल की जाएगी। निगम की इस कार्रवाई से उन हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।

हितग्राहियों के सामने निर्माण शुरू करने की चुनौती

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में राशि जारी होने के महीनों बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होना योजना के क्रियाव्यवहार पर सवाल खड़े करता है। हालांकि, संबंधित हितग्राहियों द्वारा निर्माण शुरू नहीं करने के वास्तविक कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या सभी 232 हितग्राहियों को निर्माण में देरी के लिए समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है या इसके पीछे अलग-अलग कारण हैं।फिलहाल, निगम प्रशासन ने हितग्राहियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे बिना देरी किए अपने स्वीकृत आवासों का निर्माण शुरू करें। अन्यथा उन्हें योजना की स्वीकृति निरस्त होने के साथ ही पहली किशत की एक लाख रुपये की राशि वापस करने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

सौसर में अवैध शराब के अड़ों पर आबकारी विभाग की दबिश, 1800 किलो महुआ लाहन नष्ट

मेहराखापा और सीतापार के जंगलों में कार्रवाई, 30 लीटर हाथभट्टी शराब जलत; तीन प्रकरण दर्ज

विंध्य सत्ता,पांडुर्णा । जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सौसर क्षेत्र के ग्राम मेहराखापा और सीतापार में कार्रवाई की। शनिवार को की गई इस कार्रवाई के दौरान जंगल और नालों के आसपास छापड़ियों के पास पत्तियों में छिपाकर रखा गया करीब 1800 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया गया। मौके से 30 लीटर हाथभट्टी से तैयार कच्ची शराब भी जलत की गई। विभाग ने मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के



तहत तीन प्रकरण दर्ज किए हैं। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों पर दबिश दी। तलाशी के दौरान नालों और जंगल की झाड़ियों

के पास पत्तियों में महुआ लाहन एकत्र कर रखा गया था। टीम ने मौके पर ही लगभग 1800 किलोग्राम लाहन नष्ट कर दिया, ताकि इसका इस्तेमाल शराब बनाने में नहीं किया जा सके। इसके साथ ही 30 लीटर कच्ची शराब जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई कलेक्टर

और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान आबकारी वृत्त प्रभारी भारती गौड़ के साथ आरक्षक जितेंद्र धुवें और भावना हेड्डाऊ मौजूद रहे। विभाग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च) के तहत कुल तीन प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। जंगल और नालों के आसपास छिपाकर रखे गए महुआ लाहन की बड़ी मात्रा मिलने से क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण पर निगरानी की आवश्यकता भी सामने आती है। आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

20 वर्षों से अटूट आस्था की परंपरा, मां हिंगलाज को अर्पित की 51 मीटर लंबी चुनरी

पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने विधि-विधान से की पूजा-अर्चना, क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि की कामना

विंध्य सत्ता,परासिया/छिंदवाड़ा। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां हिंगलाज के प्रति श्रद्धा और आस्था की दो दशक पुरानी परंपरा इस वर्ष भी निभाई गई। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने मां हिंगलाज को 51 मीटर लंबी चुनरी अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पिछले 20 वर्षों से लगातार निभाई जा रही यह परंपरा क्षेत्र में धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी हुई है।धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धेश्वरी माता मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया मां हिंगलाज मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी को 51 मीटर लंबी चुनरी अर्पित कर दर्शन किए। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ पूजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की उन्नति, जनकल्याण और सभी परिवारों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। माता रानी की आराधना के साथ छोटी-छोटी कन्याओं को चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्याओं के सम्मान की परंपरा के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। आयोजन के माध्यम से क्षेत्र में सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की गई।



नकुलनाथ और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में लौटे अमित सक्सेना

विंध्य सत्ता छिंदवाड़ा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना की कांग्रेस में वापसी के बाद छिंदवाड़ा जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे अमित सक्सेना ने पूर्व सांसद नकुलनाथ, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकेते, नगर निगम अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनकी घर वापसी को जिले की राजनीति में बदलते समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है। अमित सक्सेना की वापसी ने भाजपा के संगठनात्मक हालात और पुराने कार्यकर्ताओं की भूमिका को

लेकर भी चर्चा छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा अपने पुराने और सर्पित कार्यकर्ताओं को वह सम्मान दे पा रही है, जिसकी अपेक्षा लंबे समय से पार्टी के साथ खड़े कार्यकर्ताओं को रहती है। भाजपा को अनुशासित संगठन के रूप में जाना जाता है, जहां कार्यकर्ताओं की भूमिका और संगठनात्मक व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, पार्टी के भीतर पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान और नए शामिल होने वाले नेताओं की भूमिका को लेकर समय-समय पर असंतोष की चर्चाएं सामने आती रही हैं।



नरेंद्र राव 7 ताभिया ब्यूरो

विंध्य सत्ता,छिंदवाड़ा । सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा पातालकोट इन दिनों देशभर से आए ट्रेकर्स के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जिला प्रशासन और इंडिया हार्डक्स के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर का ट्रेकिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चार दिवसीय इस रोमांचक यात्रा में देश के अलग-अलग महानगरों से आए 20 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस समूह में 23 वर्ष के युवा से लेकर 76 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल हैं, जो दुर्गम पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों के बीच प्रकृति को

करीब से महसूस कर रहे हैं।लगभग 25 किलोमीटर लंबे ट्रेकिंग मार्ग पर प्रतिभागी पातालकोट की गहराई में दूधी नदी के किनारे राजाखोह क्षेत्र में रेत, चट्टानों, पहाड़ों और जंगलों के बीच समय बिता रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस इलाके में ट्रेकर्स को शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर रहने और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। पुणे, गुरुग्राम, चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागी स्थानीय गाइडों के साथ इस यात्रा को पूरा कर



रहे हैं। चिमटीपुर पहुंचने पर ट्रेकर्स का स्थानीय स्तर पर आत्मीय स्वागत किया गया। पातालकोट की यह यात्रा केवल पहाड़ों पर चढ़ने और जंगलों में घूमने तक सीमित नहीं है। ट्रेकर्स यहां के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली, रीति-रिवाजों, अनुभव प्रकृति से जुड़ने के साथ-साथ स्थानीय समाज को समझने का माध्यम भी बन रहा है। ऐसे आयोजनों से पातालकोट की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने और क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है।पातालकोट में ट्रेकिंग

गतिविधियों का आयोजन पर्यटन विकास के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय गाइडों की सेवाएं लेने और क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यदि इस तरह की गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित होती हैं, तो स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन से जुड़े नए काम के रास्ते खुल सकते हैं।

कलेक्टर हर्देद नारायण और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिम कुमार के मार्गदर्शन में जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी पहल के तहत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जिला प्रशासन और इंडिया हार्डक्स ने पातालकोट में ट्रेकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध पातालकोट में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ट्रेकिंग कार्यक्रम को प्लास्टिक मुक्त रखने की पहल की गई है। प्रतिभागियों को प्लास्टिक कचरा नहीं फैलाने, पेड़-पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने और क्षेत्र की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ट्रेकर्स भी इस पहल में सहयोग करते हुए अपने साथियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने का संदेश दे रहे हैं।

छुहिया घाटी कांड का 30 हजार का इनामी तीसरा आरोपी संजय पटेल गिरफ्तार

मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा के पास पुलिस ने की घेराबंदी, भागने के प्रयास में मोटरसाइकिल से गिरा आरोपी

उड़ीसा पुलिस दल पर हमला कर बंदी को छुड़ाकर ले जाने के मामले में सीधी पुलिस की कार्रवाई, घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती

विंध्य सत्ता,सीधी। छुहिया घाटी में उड़ीसा पुलिस दल पर हमला कर पुलिस अभिरक्षा से बंदी आदित्य मिश्रा को छुड़ाकर ले जाने के बहुचर्चित मामले में सीधी पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने २30 हजार के इनामी फरार आरोपी संजय पटेल (30 वर्ष), निवासी कुड़्यूँ कला, थाना मन्गवां, जिला रीवा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी है। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने मुखबि्र की सूचना और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा के पास कार्रवाई की।

घेराबंदी के दौरान भागने लगा आरोपी



पुलिस के अनुसार, फरार इनामी आरोपी की तलाश के दौरान उसकी मौजूदगी की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने सीमा क्षेत्र के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी मोटरसाइकिल से भागने लगा।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में

पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया। इसी दौरान आरोपी की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। घटना में घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पूछताछ में घटना में भूमिका की जानकारी

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने छुहिया घाटी में उड़ीसा पुलिस दल पर हमला करने और बंदी को छुड़ाकर ले जाने की घटना में अपनी भूमिका के संबंध में जानकारी दी है। पुलिस उसके कथनों का उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण कर रही है। मामले में अन्य फरार

कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत के निर्देशन, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा रंज हेमंत चौहान के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के नेतृत्व में सीधी एवं रीवा पुलिस के समन्वित प्रयासों से की गई।

पुलिस टीम का रहा सराहनीय योगदान

कार्रवाई में थाना प्रभारी रामपुर नैकिन निरीक्षक सुधाशु तिवारी, उपनिरीक्षक शेषमणि मिश्रा, प्रधान आरक्षक प्रसन्न मिश्रा एवं धीरेन्द्र सिंह, आरक्षक लक्ष्मीकांत पाण्डेय, सचिन साहू एवं विवेक द्विवेदी, नायक शशिशेखर उपाध्याय तथा साइबर सेल के कृष्ण मुरारी दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण विवरण: थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्रमांक 1000/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं आर्मस् एक्ट की धारा 25/27 के अंतर्गत मामला दर्ज है। पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की विवेचना और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

सीधी जिले के 134 चयनित ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को मत्स्यपालन पर मिलेगा 90 प्रतिशत अनुदान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के उत्कर्ष अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि

विंध्य सत्ता,सीधी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत सीधी जिले के चयनित 134 ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक हितग्राहियों से मत्स्यपालन आधारित रोजगार एवं स्वरोजगार गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य जनजातीय हितग्राहियों को मत्स्यपालन के लाभकारी व्यवसाय से जोड़कर उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाना है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग दीपक शुक्ला ने बताया कि योजना के तहत बैकयार्ड मिनी आरएएस, बायोफ्लॉक, पॉन्ड बायोफ्लॉक, मछली विक्रय के लिए साइकिल, आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल एवं ऑटोरिक्शा, संवर्धन पोखर निर्माण, फिश कियोस्क सहित अन्य गतिविधियों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत इकाई लागत की 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में देय होगी। कार्य पूर्ण होने तथा मूल्यांकन के उपरांत अनुदान की राशि शासन द्वारा सीधे हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। यह योजना केवल सीधी जिले के चयनित 134 ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए संचालित है। इच्छुक पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के लिए इच्छुक हितग्राही कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला सीधी, वीथिका परिसर, खनिज विभाग के बगल में संपर्क कर सकते हैं।

जूरी गांव के 6 आंगनबाड़ी केंद्रों में एक साल से नहीं मिल रहा पोषण आहार, बच्चों की उपस्थिति घटी

परियोजना अधिकारी ने जताई अनभिज्ञता, कार्यकर्ताओं का दावा—वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जानकारी; ग्रामीणों ने की जांच की मांग

विंध्य सत्ता,कुसमी/सीधी। सीधी जिले के महिला एवं बाल विकास परियोजना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जूरी के छह आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पिछले करीब एक साल से पोषण आहार एवं मध्याह्न भोजन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि समूहों द्वारा भोजन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति लगातार घट रही है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार, जूरी गांव के छह आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नियमित रूप से पोषण आहार एवं मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसका असर बच्चों के पोषण और आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर पड़ रहा है। वहीं, गर्भवती एवं धारी महिलाओं को मिलने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) की व्यवस्था भी प्रभावित होने की बात सामने आई है।

एक साल से भोजन नहीं मिलने का दावा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा सिंह ने बताया कि उनके केंद्र में करीब एक साल से समूहों द्वारा मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं करया गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से संबंधित



जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। कार्यकर्ताओं के अनुसार, भोजन और पोषण आहार की व्यवस्था प्रभावित होने से बच्चे तथा गर्भवती एवं धारी महिलाएं भी केंद्रों पर कम पहुंच रही हैं।

परियोजना अधिकारी ने कहा—जानकारी नहीं है

मामले को लेकर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी माया गिरी से बात की गई तो उन्होंने इस समस्या की जानकारी

नहीं होने की बात कही। उन्होंने संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक से जानकारी लेने की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि छह आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबे समय से पोषण आहार एवं भोजन वितरण प्रभावित है, तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची और अब तक समाधान क्यों नहीं किया गया।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की जांच की मांग

मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) एवं जिला कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जूरी गांव के सभी छह आंगनबाड़ी केंद्रों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही, बच्चों को नियमित पोषण आहार एवं भोजन उपलब्ध कराने तथा गर्भवती एवं धारी महिलाओं के लिए टीएचआर वितरण व्यवस्था सुचारु करने की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और बच्चों के पोषण से जुड़ी इस समस्या का समाधान कब तक किया जाता है।

सीधी में बीएसी और जनशिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए काउंसिलिंग 22 अक्टूबर को

पात्र उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक ले सेकेंगे भाग, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर विंध्य सत्ता,सीधी। जिला शिक्षा केन्द्र सीधी द्वारा विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (बीएसी) एवं जनशिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पंजीयन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र विनय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में बीएसी के पांच पदों तथा प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र में दो जनशिक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही की जाएगी। बीएसी के पांच पदों में विज्ञान संकाय के दो, सामाजिक विज्ञान संकाय का एक तथा भाषा संकाय के दो पद शामिल हैं। भाषा संकाय के दो पदों में एक पद अंग्रेजी विषय के लिए अनिवार्य होगा।

पदों के लिए निर्धारित पात्रता

बीएसी एवं जनशिक्षक पदों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षक अथवा माध्यमिक शिक्षक पात्र होंगे। आवेदक की आयु 1 जनवरी की स्थिति में 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा लंबे समय से लगातार अनुपस्थित रहने संबंधी शिकायत प्रचलित नहीं होनी चाहिए।

सफलता की कहानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अशोक गुप्ता ने पुनः स्थापित किया स्वरोजगार

कोरोना काल में प्रभावित हुआ व्यवसाय, ऋण सहायता से फिर संभली आजीविका

विंध्य सत्ता,सीधी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जल्दतम पथ विक्रेताओं के लिए स्वरोजगार को पुनः स्थापित करने में मददगार साबित हो रही है। नगर पालिका परियद सीधी के वार्ड क्रमांक 19 निवासी अशोक गुप्ता ने योजना के तहत ऋण सहायता प्राप्त कर अपने व्यवसाय को फिर से स्थापित किया है। आज बैंग एवं कपड़ों का उनका व्यवसाय परिवार के भरण-पोषण का सहारा बना हुआ है। अशोक गुप्ता मानस भवन के सामने फुटपाथ पर बैंग एवं कपड़ों की दुकान लगाकर अपना परिवार चलाते थे। कोरोना काल में दुकान बंद होने के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ऐसी परिस्थिति में व्यवसाय को दोबारा शुरू करना उनके लिए चुनौती बन गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें 10 हजार रुपये एवं 20 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहायता से उन्होंने अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित किया। धीरे-धीरे उनका काम आगे बढ़ा और अब व्यवसाय अच्छी तरह संचालित हो रहा है। इससे उन्हें आजीविका का साधन प्राप्त हुआ है और परिवार के जीवन-यापन में मदद मिल रही है। अशोक गुप्ता ने योजना से मिली सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। योजना से मिली ऋण सहायता ने उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने और दोबारा आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया।



नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्र मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्र रीपर या बेलेर का उपयोग अनिवार्य

विंध्य सत्ता,सीधी। जिले में नरवाई एवं पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आर एस गुप्ता ने बताया कि आदेश के तहत फसल कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्र मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्र रीपर या बेलेर में से किसी एक मशीन का उपयोग अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि धान एवं गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इससे मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीवों एवं जैविक कार्बन को नुकसान पहुंचता है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। इसे देखते हुए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भूमि के रकबे के अनुसार लंगंगा जुर्माना

खास खबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ कार्यक्रम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक

ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर बीमित किसानों को वितरित की जाएगी फसल बीमा पॉलिसियां

विंध्य सत्ता,सीधी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ कार्यक्रम का आयोजन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बीमित किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के साथ योजना के प्रावधानों एवं लाभों के प्रति जागरूक करना है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आर.एस. गुप्ता ने बताया कि केंद्र एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में बीमित किसानों को फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा तथा योजना की पात्रता, बीमा सुरक्षा, लाभ एवं फसल क्षति की स्थिति में दावा प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

विभिन्न विभागों की रहेगी सहभागिता

कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत संस्थाओं, बैंकों, बीमा कंपनियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पॉलिसी वितरण की नियमित मॉनिटरिंग, दैनिक रिपोर्टिंग तथा पर्याप्त मात्रा में पॉलिसियों एवं प्रचार-प्रसार सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। योजना की व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाएगा।

वन अधिकार अधिनियम के पात्र किसानों को प्राथमिकता

शासन के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत आने वाले पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंच सके।उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों में सहभागिता कर अपनी फसल बीमा पॉलिसी प्राप्त करें तथा योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी लें। इस पहल से किसानों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और योजना का लाभ पात्र कृषकों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

कुसमी में प्राचार्यों एवं जनशिक्षकों की समीक्षा बैठक आयोजित

शैक्षणिक गुणवत्ता और योजनाओं के क्रियान्वयन की सहायक आयुक्त ने की समीक्षा

विंध्य सत्ता,सीधी। विकासखंड कुसमी के समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों तथा जनशिक्षकों की समीक्षा बैठक पीएम श्री विद्यालय टमसार में आयोजित की गई। बैठक में सहायक आयुक्त केके पाण्डेय द्वारा विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विद्वान समीक्षा की गई। बैठक में निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति, एफएलएन कक्षाओं के संचालन एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए विद्यार्थियों के बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम की पूर्णता तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों की विद्यालयवार जानकारी भी ली गई।

विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रगति पर जोर

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्थिति की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चों की जानकारी तथा इसके कारणों पर चर्चा की गई। साथ ही छात्रवृत्ति वितरण और अपार आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों की



संचालन, साक्षरता परीक्षा की तैयारी एवं प्रगति पर चर्चा की गई। शत-प्रतिशत पात्र लोगों को साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई।

विद्यालयों की सुविधाओं एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के निर्देश

विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा के दौरान क्रियाशील शौचालयों, विद्यालय भवनों की स्थिति, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। प्राचार्यों को उपलब्ध संसाधनों का विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

संक्षिप्त समाचार

कुशाग्र को क्रिकेटर बनाने के लिए पिता ने खुद सीखी बैटिंग

नई दिल्ली। कुमार कुशाग्र के पिता शशिकान्त ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए खुद बल्लेबाजी की तकनीक सीखी। जेएनयू में इतिहासकार रोमिला थापर से मिली शोध को सीख को क्रिकेट में अपनाते हुए उन्होंने किताबों, वीडियो और लगातार अभ्यास के जरिए बेटे को प्रशिक्षित किया। 15 साल की मेहनत के बाद कुमार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया। किसी पिता का सपना होता है कि उसका बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन जब बेटे की आंखों में उस सपने की चमक तक न हो, तब उसे हकीकत में बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? झारखंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र की कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां एक पिता ने न सिर्फ बेटे के लिए सपना देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए खुद क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। उन्हें न क्रिकेट खेलने का अनुभव था और न ही कोचिंग का कोई औपचारिक प्रशिक्षण। फिर भी उन्होंने किताबें पढ़ीं, बड़े खिलाड़ियों के खेल का अध्ययन किया और अपने बेटे को बल्लेबाजी के गुर सिखाने में जिंदगी के 15 साल लगा दिए।

दिल्ली कैपिटल्स का एक और बड़ा दांव!

नई दिल्ली।दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2027 से पहले श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चर्मिंडा वास को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। इससे पहले सौरव गांगुली को मुख्य कोच और युवराज सिंह को सहायक एवं बल्लेबाजी कोच बनाया गया था। नए कोचिंग स्टाफ के साथ दिल्ली की नजर पहली बार आईपीएल खिताब जीतने पर होगी। आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कोचिंग स्टाफ को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। फ्रेंचाइजी ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज चर्मिंडा वास को टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। इससे पहले दिल्ली सौरव गांगुली को मुख्य कोच और युवराज सिंह को सहायक एवं बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंप चुकी है। अब वास के जुड़ने से टीम के कोचिंग स्टाफ में अंतरराष्ट्रीय अनुभव का एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए वास की नियुक्ति की घोषणा की।

डोपिंग में फंसे भारतीय पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने भारतीय पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ पर प्रतिबंधित स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद तीन साल का प्रतिबंध लगाया है। उनका प्रतिबंध 24 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2029 तक लागू रहेगा। नई दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में उनके सभी नतीजे रद्द कर दिए गए हैं और पदक, अंक व पुरस्कार भी वापस लिए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) ने भारतीय पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अनमोल इस साल मार्च में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के दौरान प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी के बयान के अनुसार, अनमोल के मूत्र के नमूने में डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइल-टेस्टोस्टेरोन (डीएफसीएमटी) के मेटाबोलाइट की मौजूदगी पाई गई। यह नमूना 11 मार्च को पुरुषों की जैवतिलन श्रो एफएस5 स्पर्धा के दौरान प्रतियोगिता के बीच लिया गया था।

क्या विरोध प्रदर्शनों के चलते बदला दिल्ली हाफ मैराथन का रूट ?

नई दिल्ली। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच रविवार को होने वाली वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के मार्ग में मामूली बदलाव किया गया है। धावक अब रेल भवन, संसद मार्ग और पटेल चौक से होकर नहीं गुजरेंगे। वहाँ, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की दौड़ सुवह सात बजे के बजाय 6:30 बजे शुरू होगी। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों का असर वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन पर भी पड़ा है। रविवार को आयोजित होने वाली इस दौड़ के आयोजकों ने शुक्रवार को मार्ग में मामूली बदलाव की घोषणा की। नए मार्ग के तहत धावक रेल भवन, संसद मार्ग और पटेल चौक से होकर नहीं गुजरेंगे। इन स्थानों के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। ये तीनों स्थान पिछले वर्षों में हाफ मैराथन के पारंपरिक मार्ग का हिस्सा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार, इस बार हाफ मैराथन के 10 से 13 किलोमीटर के बीच के हिस्से में बदलाव किया गया है।



कैफ ने दिया सफलता का मंत्र..

चिन्नास्वामी में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

खेल एजेंसी **बंगलूरू।** भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला शनिवार को बंगलूरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर भारत ने आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में चार जीते, तीन गंवाए और एक बेनतीजा रहा। सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबर है। भारत ने यहां अपना पिछला टी20 मुकाबला 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसका फैसला दो सुपर ओवर के बाद हुआ था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शनिवार को बंगलूरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आइए आपको बताते हैं इस मैदान पर टीम



इंडिया का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में रिकॉर्ड कैसा रहा है। भारतीय टीम ने चिन्नास्वामी के मैदान पर अब तक कुल आठ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने चार मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि तीन मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। भारतीय टीम ने इस ग्राउंड पर

अपना आखिरी मुकाबला साल 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। इस मैच का नतीजा दो सुपर ओवर खेलने के बाद निकला था, जहां टीम इंडिया बाजी मारने में सफल रही थी। पांच मैचों की टी20 सीरीज अभी 2-2 की बराबर है। चौथे टी20 मुकाबले में कैरेबियाई टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था और उन्होंने 24 रनों से जीत दर्ज की

जयवर्धने ने छोड़ा मुंबई इंडियंस का साथ, कोच पद से दिया इस्तीफा रोहित के फि्ट कप्तान बनने की चर्चा

खेल एजेंसी **मुंबई।**मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 से पहले महेला जयवर्धने के मुख्य कोच का पद छोड़ने की घोषणा की है। उनके दो कार्यकाल में टीम ने तीन आईपीएल खिताब जीते। फ्रेंचाइजी में बदलाव के बीच रोहित शर्मा को कप्तानी को लेकर चर्चा बढ़ सकती है, लेकिन टीम ने उनकी भूमिका पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। फ्रेंचाइजी ने 17 अक्टूबर को महेला जयवर्धने के मुख्य कोच का पद छोड़ने की घोषणा की। उनके जाने के साथ ही टीम के अगले कदम और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि, मुंबई इंडियंस ने रोहित की भूमिका को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जयवर्धने का मुंबई इंडियंस के साथ एक दशक से अधिक समय तक जुड़ाव रहा। इस दौरान उन्होंने मुख्य कोच के रूप में तीन आईपीएल खिताब जीतने में टीम की मदद की। फ्रेंचाइजी ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा



कि उन्होंने टीम की संस्कृति बनाने, खिलाड़ियों के बीच मजबूत तालमेल कायम करने और अनुशासन के साथ टीम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में दो कार्यकाल में काम किया। उनका पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा, जबकि वह 2024 से 2026 के बीच फिर इस जिम्मेदारी में लौटे। उनके नेतृत्व में टीम ने तीन बार आईपीएल का खिताब जीता। टीम 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनी। हालांकि, इसके बाद मुंबई का प्रदर्शन कुछ खराब नहीं रहा है। मुंबई इंडियंस की ओर से जारी बयान में टीम की मालकिन नीता अंबानी ने जयवर्धने के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, महेला ने वर्षों से मुंबई इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके शांत नेतृत्व, ईमानदारी और खेल के प्रति गहरे लगाव का हमारे लिए बहुत महत्व रहा है। पूरे एमआई परिवार की ओर से मैं उनके योगदान और वर्षों तक अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ।

कौन हैं कात्या मारन और क्यों चर्चा में?

करोड़ों का साम्राज्य और ग्लैमरस बॉस! किस राजनीतिक परिवार से है नाता

खेल एजेंसी **नई दिल्ली।** सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और सह-मालिक कात्या मारन संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ शादी की चर्चाओं के कारण सुर्खियों में हैं। कारोबारी परिवार में जन्मी कात्या ने एमबीए के बाद सन रूफ और क्रिकेट फ्रेंचाइजी में अहम भूमिका निभाई। मैदान पर उनकी लोकप्रियता और टीम के प्रति जुनून ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। आईपीएल में जब सनराइजर्स हैदराबाद का कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है, तो स्टैंड्स और ड्याआउट में बैठी कात्या मारन की खुशी कैमरों में कैद हो जाती है। टीम हारती है, तो उनके चेहरे की मायूसी भी सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरती है। क्रिकेट के मैदान से मिली इसी पहचान के बीच अब कात्या की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में है। सन रूफ के प्रमुख

कलानिधि मारन की बेटी कात्या मारन मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दोनों की शादी के रिसेशन की पुष्टि की है। चेन्नई में 21 नवंबर को होने वाले इस समारोह के लिए मारन परिवार ने मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है। हालांकि, शादी की तारीख की अभी पुष्टि नहीं हुई है। शादी प्रीस में हो सकती है। क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कात्या की जिंदगी का यह नया अध्याय उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है। एक तरफ करोड़ों का कारोबारी साम्राज्य, दूसरी तरफ आईपीएल में अपनी टीम के लिए जुनून और अब दक्षिण भारतीय संगीत जगत के चर्चित नाम अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ



शादी। कात्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद (स्कआ) की सीईओ और सह-मालिक हैं। वह सन रूफ के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की बेटी हैं। क्रिकेट में उनकी लोकप्रियता आईपीएल के दौरान बढ़ी, जब मैचों और नीलामी के दौरान उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार कैमरों में दिखाई देने लगीं। हालांकि, उनकी पहचान

शामिल हैं, जिनका क्रिकेट सलाहकार समिति ने वर्चुअल इंटरव्यू लिया है। इस पद के लिए पूर्व भारतीय स्पिनर रमेश पोवार, पूर्व तेज गेंदबाज सलिल अंकोला और बड़ौदा के पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन व कॉनर विलियम्स के नाम भी सामने आए हैं। इस बीच, इस पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे पार्थिव पटेल ने आवेदन नहीं किया। अब क्रिकेट सलाहकार समिति को पांचवें चयनकर्ता के नाम पर अंतिम फैसला करना है।

सीनियर पुरुष चयन समिति में यह पद अजीत अगरकर के मुख्य चयनकर्ता पद से हटने के बाद खाली हुआ। इसके बाद बीसीसीआई ने नए चयनकर्ता की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। फिलहाल पूर्व भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर चयन समिति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नए

थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 247 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम भी विकेट गंवाकर 223 रन ही बना सकी थी। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय 102 खेती थी और वह 50 गेंदों में 112 रन बनाकर नाबाद रहे थे। भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के आगे चौथे टी20 में पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए थे। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 43 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 41 रनों का योगदान दिया था। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज के लिए कीमती पोल ने चार ओवर के स्पेल में 41 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए थे।

चार मैचों में बेंच पर बैठे! पांचवें टी20 से पहले वैभव ने ऐसा क्या लिखा, जिससे सब चौंके ?

खेल एजेंसी **बंगलूरू।**वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती चार टी20 मुकाबलों में मौका नहीं मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने स्टिल बिलीविंग पोस्ट साझा की। सीरीज 2-2 से बराबर है। कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि वैभव को अवसर का इंतजार करना होगा, क्योंकि टीम संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पर भरोसा कर रही है। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती चारों मुकाबलों में 15 वर्षीय वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। अब सीरीज 2-2 से बराबर है और शनिवार को होने वाले पांचवें व निर्णायक टी20 मुकाबले से पहले वैभव की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है।



उन्होंने लिखा, स्टिल बिलीविंग यानी अब भी भरोसा है। उनके इस संदेश को टीम में मौका मिलने की उम्मीद से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम प्रबंधन ने अब तक संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी जोड़ी पर भरोसा जताया है। इसी वजह से वैभव को लगातार बेंच पर बैठना पड़ा है। सीरीज बराबर होने के बाद पांचवें मुकाबले का महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में कप्तान

श्रेयस अय्यर और कोच गंभीर के सामने टीम संयोजन को लेकर फैसला लेने का विकल्प होगा। हालांकि, वैभव की पोस्ट से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह खराब तौर पर पांचवें टी20 में खेलने की बात कर रहे थे। लेकिन चार मुकाबलों में मौका नहीं मिलने के बाद उनका स्टिल बिलीविंग लिखना उनके इंतजार और उम्मीद की ओर इशारा करता है। गौतम गंभीर ने वैभव को मौका नहीं मिलने पर अपना पक्ष

भुवनेश्वर की कमबैक स्टोरी : 2022 में खेला था पिछला मैच, चार साल का इंतजार और चोटों से जंग! फिर बनेंगे संकटमोचक?

खेल एजेंसी **बंगलूरू।**करीब चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद लगाए भुवनेश्वर कुमार वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्णायक टी20 में खेल सकते हैं। क्रिकेट के प्रति उनकी दिलचस्पी और उनकी उपलब्धता निर्भर करेगी। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन, स्विंग, धीमी गेंदों पर नियंत्रण और अनुभव उन्हें भारत की गेंदबाजी के लिए अहम विकल्प बनाते हैं। कुछ खिलाड़ियों का करियर सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और वापसी की कहानियों से याद किया जाता है। भुवनेश्वर को वापसी में ऐसे ही गेंदबाज हैं। अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले भुवनेश्वर ने चोटों, टीम से बाहर होने और लंबे इंतजार के बीच भी क्रिकेट से अपना रिश्ता नहीं टूटने दिया। अब करीब चार साल बाद भारतीय टीम में उनकी वापसी का रास्ता खुलता नजर

तहत ही होगा। वसीम जाफर भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 19 हजार से अधिक रन बनाए हैं। वह मुंबई और विदर्भ की ओर से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में भी अहम योगदान दे चुके हैं। जाफर का अनुभव सिर्फ खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहा है। वह आईपीएल में कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की अंडर-19 टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं। वह विदर्भ के सलाहकार रहे हैं और 2026-27 के घरेलू सत्र में हैदराबाद टीम के मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। घरेलू क्रिकेट का लंबा अनुभव और कोचिंग से जुड़ाव उनकी दावेदारी को चर्चा में बनाए हुए है। वसीम जाफर के अलावा रमेश पोवार और सलिल अंकोला भी सीनियर चयन समिति के खाली पद के लिए इंटरव्यू देने वाले प्रमुख नामों में शामिल हैं।

कैफ ने दिया सफलता का मंत्र : बताया- 1983-2011 और 2024 की विश्वकप जीत में क्या था एक जैसा, जिससे सीखे मौजूदा टीम

खेल एजेंसी **बंगलूरू।** मोहम्मद कैफ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी के प्रदर्शन पर चिंता जताते हुए 1983, 2011 और 2024 के विश्व कप फाइनल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि खिताब जीतने के लिए मजबूत गेंदबाजी जरूरी है। कैफ ने गेंदबाजों को लगातार मौके देने और कप्तान श्रेयस अय्यर से आक्रामक रणनीति अपनाने की अपील की। भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतना है तो उसे अपनी गेंदबाजी मजबूत करनी होगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए टीम को गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, अगर आप 1983 विश्व कप का फाइनल देखें तो हमने अपनी गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की थी।

गेंदबाजी आक्रमण जरूरी है और कप्तान की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी टीम तैयार करे। वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भारतीय गेंदबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। अनुभव की कमी के साथ दबाव में सही गेंद खलने और योजनाओं को सटीक तरीके से लागू करने में भी टीम जूझती दिखी है। कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि इतिहास गवाह है कि अच्छी गेंदबाजी करने वाली टीमों में ही बड़े खिताब जीतती हैं। कैफ ने 1983, 2011 और 2024 के विश्व कप फाइनल का उदाहरण देते हुए कहा कि इन तीनों खिताबी जीत में भारतीय गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, अगर आप 1983 विश्व कप का फाइनल देखें तो हमने अपनी गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की थी।



कलेक्टर ने कोष्टा और भुंडहा में अवैध कालोनी बनाने वालों पर दिए कार्रवाई के आदेश

अवैध कालोनी बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करके होगी कार्रवाई

विंध्य सत्ता,रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डीधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने ग्राम कोष्टा तथा भुण्डहा में अवैध कालोनी बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अलग-अलग जारी आदेशों के अनुसार पटवारी हल्का कोष्टा के ग्राम भुंडहा में खसरा नम्बर 381/1/1, 382, 383/1, 383/2 तथा 384 में अवैध कालोनी बनाने वाले अशोक कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, रूपेश कुमार सिन्हा सभी निवासी पाड़ुन टोला के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह एक अन्य आदेश में ग्राम कोष्टा के 14 भूमि स्वामियों बसंतराम तिवारी, अवध प्रसाद तिवारी, श्रीनिवास सिंह, श्रीमती सोनवती तिवारी, बृजेश तिवारी, बैजनाथ तिवारी, राजकुमार तिवारी, निरंजन तिवारी, ज्योति तिवारी, अमृत कुमार तिवारी, श्रीमती स्नेहलता तिवारी, विजय कुमार तिवारी तथा करण तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि इन सभी व्यक्तियों ने जमीन का डायवर्सन कराए बिना कृषि भूमि में छोटे-छोटे आवासीय प्लाट



बनाकर लोगों को बेचा, जिन पर खरीदने वालों ने मकान बनाए हैं। कालोनी बनाने के लिए कालोनाईजर्स एक्ट के तहत अनुमति नहीं ली गई है। अवैध कालोनी में पानी, बिजली, सड़क और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अवैध कालोनी बनाने के कारण शासन को आश्रय शुल्क की हानि हुई है जो आर्थिक

ग्राम निवेश विभाग के अधिनियम, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि एसडीएम रायपुर कर्चुलियान अवैध कालोनी बनाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें। इनके विरुद्ध भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के

अनियमितता की श्रेणी में आता है। इन दोनों कालोनियों में रहने वाले निवासियों द्वारा कालोनाईजर्स से कालोनी में मूलभूत सुविधाओं की लगातार मांग की जा रही है किन्तु उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अवैध कालोनी बनाकर आरोपियों ने मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 तथा नगर एवं पंचायत सचिव कोष्टा इन अवैध कालोनियों में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति जारी न करें। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति निर्माण करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान राजस्व रिकार्ड में अवैध कालोनी वाली जमीनों के खसरे के कालम नम्बर 12 में अवैध कालोनी दर्ज करें। इन जमीनों के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही न करें। अवैध कालोनी में रहने वाले निवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए अवैध कालोनी बनाने वाले भूमि स्वामियों की अन्य स्थानों पर स्थित भूमि तथा कालोनी में अविक्रित भूमि को तहसीलदार कुर्क करके कब्जे में लें। अवैध कालोनी बनाने वालों से आश्रय शुल्क की वसूली के लिए समुचित कार्यवाही करें। जिला पंजीयक भविष्य में अवैध कालोनी में स्थित किसी भी प्लाट के क्रय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन न करें। अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल अवैध कालोनी में बिजली के नए कनेक्शन जारी न करें।

रेलवे ब्रिज पर लापरवाही बनी हदसे की वजह! सड़क पर बिखरी गिट्टी से फिसली बाइक, पुलिसकर्मों घायल

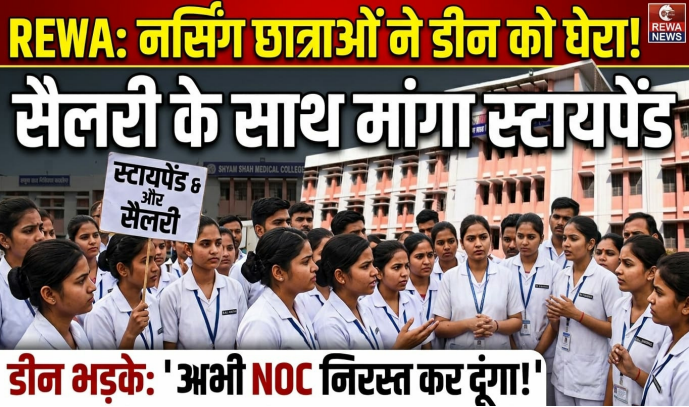
विंध्य सत्ता, रीवा। रीवा शहर के रेलवे ब्रिज पर सड़क मरम्मत के दौरान बरती जा रही लापरवाही वाहन चालकों के लिए खतरा बन गई है। सड़क से डामर उखाड़ने के बाद निकला मलबा और गिट्टी बीच सड़क पर फैले होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसी दौरान सड़क पर फैली गिट्टी पर बाइक फिसलने से पुलिसकर्मों रामकरण सिंह घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक, रेलवे ब्रिज पर जेसीबी मशीन की मदद से डामर सड़क को उखाड़ने का काम किया जा रहा था। इस दौरान सड़क पर फैली गिट्टी और मलबे को व्यवस्थित तरीके से हटाने के बजाय उसे सड़क पर ही छोड़ दिया गया। इसी मार्ग से गुजर रहे बाइक सवार पुलिसकर्मों रामकरण सिंह की बाइक अचानक गिट्टी पर फिसल गई, जिससे उनका संतुलन



बिगड़ गया और वे सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय पहुंचाया गया। घायल पुलिसकर्मों रामकरण सिंह के मुताबिक, सड़क पर फैली गिट्टी पर उनकी बाइक कब फिसल गई, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक संतुलन बिगड़ने से वे सड़क पर गिर पड़े और चोटिल हो गए। इस घटना ने सड़क मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यस्त मार्ग पर सड़क की खुदाई और डामर उखाड़ने के दौरान मलबा हटाने, चेतावनी संकेतक लगाने, बैरिकेडिंग करने से संचालित करने की व्यवस्था आवश्यक है। इसके बावजूद सड़क पर गिट्टी और मलबा फैला रहने से वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने डीन को घेरा, सैलरी के साथ मांगने पहुंचे स्टायपेंड, भड़के डीन बोले अभी एनओसी कर दूंगा निरस्त

विंध्य सत्ता,रीवा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का कोर्स संचालित है। इसमें विभागीय पाठ्यक्रम भी संचालित है। अस्पताल में काम करने वाली एनएनएम विभाग की तरफ से बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जाती है। बीएससी के बाद भी कई नर्स एमएससी नर्सिंग करती है। इन नर्सों को विभाग की तरफ से पढ़ाई का अवसर तो दिया ही जाता है साथ ही वेतन भी बंद नहीं किया जाता। अब यहां पढ़ने आने वाली नर्सें अस्पताल की इयूटी से तो बच ही गई थी। पढ़ाई के नाम से उन्हें सिर्फ कॉलेज में क्लास अटेंड करना होता है। इसमें भी वह आए चाहें न आए, कोई देखने वाला नहीं होता। उन्हें अस्पताल में शिफ्ट वाली इयूटी से भी राहत मिल जाती है। सिर्फ सुबह ही कॉलेज आना पड़ता है। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी बीएससी फाइनल ईयर की नर्सों को स्टायपेंड का भूत सवार हो गया। सभी नर्सें एकजुट हुईं और सीधे डीन से मिलने पहुंच गईं। डीन से नर्सों ने स्टायपेंड दिलाने की मांग कर दी। डीन भी उनकी बातें सुन कर सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि आप सभी विभागीय नर्सें हैं। यहां एनओसी लेकर पढ़ने आई हैं। आप सभी को पढ़ाई के साथ ही नर्सिंग का वेतन भी दिया जा रहा है।



डीन भड़के: 'अभी NOC निरस्त कर दूंगा!'

वेतन के साथ स्टायपेंड दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। स्टायपेंड सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। कहीं नौकरी नहीं कर रहीं हैं। डीन ने उन्हें समझाने की कोशिश की फिर भी वह स्टायपेंड की जिद पर अड़ी रही। इस पर डीन ने साफ कह दिया कि यदि ऐसा कोई आदेश है तो दिखा दीजिए। फिर हमें स्टायपेंड देने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी कि यदि स्टायपेंड बिना पढ़ाई नहीं करनी है तो वापस काम पर लौट जाएं। सभी की एनओसी निरस्त कर

देते हैं। कम से कम दूसरों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इतना सुनने के बाद सभी नर्सें चुपचाप बिना कोई सवाल किए वापस लौट गईं।

काम के डर से पढ़ने चली आई हैं कई नर्सें, अस्पताल में पढ़ा है टोट

करीब 200 से अधिक नर्सें अस्पताल में नौकरी पाने के बाद नर्सिंग कॉलेज चली आई हैं। कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो कोई एमएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही है। वहीं जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है वह नर्सिंग कॉलेज में ही फैकल्टी का रोल निभा रही हैं। नर्सिंग कॉलेज में पद तो हैं लेकिन कोई भी पदभरा नहीं गया है। नर्सों को भी प्रोफेसर, प्रिंसिपल, लेक्चरर बनाकर काम चलाया जा रहा है। सीबीआई की जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। उसी ढंग पर व्यवस्था चल रही है। अस्पताल की नर्सों काम के डर से नर्सिंग कॉलेज आ गई हैं। वह अब वापस अस्पताल में नौकरी करने जाना ही नहीं चाहती। यही वजह है कि अस्पताल में नर्सों का फूटा पड़ा है। अब यही नर्सें स्टायपेंड भी मांग रही हैं।

नशे के खिलाफ जंग का संदेश लेकर रीवा पहुंची राष्ट्रध्वजी बाइक रैली, पुलिस अधिकारियों ने दिलाई नशामुक्ति की राध



विंध्य सत्ता, रीवा। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड-2026 के तहत संचालित राष्ट्रध्वजी बाइक रैली शनिवार को रीवा पहुंची। 'फाइट अगेस्ट ड्रग्स' (नशे के खिलाफ लड़ाई) की थीम पर निकाली जा रही इस रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज

में नशामुक्ति का संदेश प्रसारित करना है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल पुलिस बल के 46 सदस्यीय दल ने सहभागिता की। दल का नेतृत्व बिहार पुलिस के डीएसपी मिराज हुसैन कर रहे थे। रीवा आगमन पर पुलिस प्रशिक्षण शाला (पीटीएस) परिसर में

रैली के सदस्यों के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत, पुलिस उपमहानिरीक्षक हेमंत सिंह चौहान तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने नशे के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन पर

पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में जानकारी देते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, बाइक रैली के 46 सदस्यीय दल और नागरिकों को स्वयं नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी नशे के सेवन से बचाने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए टीम लीडर्स को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस प्रशिक्षण शाला परिसर में बाइक रैली के सदस्यों का आत्मीय स्वागत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नशे के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान की सराहना करते हुए इसकी सफलता की कामना की। रैली के आयोजकों से युवाओं और आम नागरिकों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने तथा स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज के निर्माण का आह्वान किया गया।

छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस पर हमले का मामला: 30 हजार का इनामी संजय पटेल गिरफ्तार



विंध्य सत्ता, रीवा।सीधी जिले की छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस दल पर हमला कर पुलिस अभिरक्षा से बंदी आदित्य मिश्रा को छुड़ाकर ले जाने के मामले में सीधी पुलिस ने 30 हजार रुपये के इनामी फरार आरोपी संजय पटेल (30) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजय पटेल निवासी कुड़या कला, थाना मनगवां, जिला रीवा का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस की ओर से की गई यह तीसरी गिरफ्तारी है। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी संजय पटेल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। आरोपी पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सीधी और रीवा पुलिस के समन्वित प्रयासों के बाद उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत के निर्देशन, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा रंज हेमंत चौहान के मार्गदर्शन तथा सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी और रीवा पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरण सिंह के नेतृत्व में की गई। मामले में पुलिस ओ को वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

आदि सेवा केन्द्रों में हर सप्ताह अलग-अलग गतिविधियों का होगा आयोजन



विंध्य सत्ता,रीवा । जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए आदि सेवा केन्द्रों का नियमित संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों में 17 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक हर सप्ताह अलग-अलग गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग केके पाण्डेय ने बताया? कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निर्धारित गतिविधियों का आदि सेवा केन्द्रों में आयोजन कराएंगे। आदि सेवा केन्द्रों में 17 से 24 अक्टूबर तक स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता, निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की गतिविधि होगी। केन्द्र में 25 से 31 अक्टूबर तक जल संरक्षण, पेयजल स्रोतों को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छता के लिए श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 1 से 8 नवम्बर तक आदि सेवा केन्द्र में वित्तीय समीक्षा, बैंकिंग, बीमा, डिजिटल साक्षरता तथा कौशल विकास की गतिविधि आयोजित की जाएगी। केन्द्र में 9 से 17 नवम्बर तक शिक्षा, छत्रवृत्ति, करियर परामर्श तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

अनिल के मसाला उद्योग से निकली सफलता की सुगंध

विंध्य सत्ता,रीवा। रीवा विकासखण्ड के निवासी अनिल सिंह ने नौकरी के पीछे भागने के बजाय स्वयं का उद्यम स्थापित करने का प्रयास किया। प्रारंभिक कठिनाईयों के बाद अनिल को उद्यम स्थापित करने में सफलता मिली। उन्होंने बताया कि मैंने उद्योग विभाग की एमएसएमई योजना के तहत मसाला उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन दिया। उद्योग विभाग द्वारा मसाला उद्योग की स्थापना के लिए दो करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया। आवश्यक मशीनों की खरीद करके उन्होंने अपने घर में ही मसाला उद्योग

स्थापित किया। इसमें मुझे 14 लाख 65 हजार रुपए का अनुदान भी मिला है। मेरी इकाई से धनिया, मिर्ची, गरम मसाला तथा अन्य मसाले तैयार किए जाते हैं। इससे 10 लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा युवाओं को स्वरोजगार का अवसर देने की योजना ने मुझे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मसाला उद्योग से सफलता की सुगंध आत्मनिर्भरता की कहानी कहती है।